www.tamsasanket.com
वर्षः 06 || अंक 152 || लखनऊ
बुधवार
02 सितम्बर 2026 || पृष्ठः 04 || मूल्यः ₹2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
https://epaper.tamsasanket.com
दैनिक
तमसा संकेत
लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित
» डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र

मौसम
सूर्योदयः 05:45
सूर्यास्तः 06:25
अधिकतमः 30°00
न्यूनतमः 26°00

पेज 07

विशेष समाचार
दुनिया जब बुरे दौर में है तब ... » पेज 04
हरीपर्वत पर फिर सड़क की ... » पेज 06
पैपराजी पर भड़कीं करीना...

नई एफआईआर भी दर्ज नहीं होंगी, कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर का मार्च वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़ी सभी एफआईआर कीं रद्द

आदेश

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से जुड़ी 13 FIR को रद्द करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुनाया। हालांकि, सरकार की ओर से बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान आपराधिक रिकॉर्ड वाले 2,873 लोग भी मौके पर पहुंचे थे। ऐसे लोगों में यदि किसी ने प्रदर्शन के दौरान मारपीट या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी घटना को अंजाम दिया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रह सकती है। सुनवाई से पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर को प्रस्तावित मार्च वापस लेने का फैसला किया। संगठन की ओर से कहा गया कि कोर्ट के आदेश और सरकार की ओर से मिले सकारात्मक भरोसे को देखते हुए मार्च स्थगित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि FIR रद्द करने का फैसला इस मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसलिए इसे दूसरे मामलों के लिए नजीर या बाध्यकारी फैसला नहीं माना जाएगा।

इस तरह कोर्ट के आदेश से आंदोलन से जुड़ी FIR को लेकर बड़ी राहत मिली है, लेकिन गंभीर आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुला रखा गया है।

>> (शेष पेज 06 पर)

अभिजीत दीपके ने कहा- यह फैसला छात्रों की जीत

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, 'अगस्त के शुरूआत में सरकार के डेलिगेशन ने हमसे बात करना बंद कर दिया था, फिर हमें लगा कि ये विश्वासघात करना चाहते हैं, इसलिए हमनें 5 सितंबर को मार्च निकालेंगे का फैसला किया। आज कोर्ट में सुनवाई हुई। पूरे देश में सारे FIR को रद्दकर दिया है। यह ऐतिहासिक पल है।' अभिजीत दीपके ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट का फैसला छात्रों की जीत है। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के खिलाफ चल रहे सभी अन्यायपूर्ण मुकदमों को खारिज कर दिया है। हमारी मांगें सुनी गई हैं और अब किसी भी छात्र को आगे ऐसी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंकलाब जिंदाबाद।'

20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों-सुरक्षाकर्मियों में झड़प हुई थी

20 जुलाई को CJP के नेतृत्व में दिल्ली में हुए मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प हुई थी। संसद की ओर बढ़ रही भीड़ को रोकने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था।

आंदोलन 20 जून को जंतर-मंतर से शुरू हुआ था। प्रधान के इस्तीफे और सरकार की ओर से CJP की दूसरी मांगें मानने के बाद 25 जुलाई को आंदोलन खत्म कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

- 20 से 25 जुलाई के बीच हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल और असम में क्रिमिनल रिकॉर्ड वालों पर केस चलते रहेंगे।
- इन 5 राज्यों को छोड़कर बाकी जगहों पर ऐसी एफआईआर में पुलिस न तो जांच आगे बढ़ाएगी और न ही कोई कार्रवाई करेगी।
- सरकार नीट पेपर लीक के कारण सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स के परिवारों को 3 महीने के अंदर मुआवजा दे।

2,873 लोगों पर कार्रवाई की छूट

दिल्ली पुलिस के अंतरिम आवेदन पर हुई सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल अंतरिम आवेदन पर सुनाया। अंतरिम आवेदन का मतलब ऐसी अर्जी से है, जो किसी मामले की मुख्य सुनवाई के दौरान किसी विशेष मुद्दे पर तत्काल आदेश या राहत की मांग के लिए दाखिल की जाती है।

सरकार ने सोमवार को यह आवेदन दाखिल किया था। इसमें कहा गया था कि 25 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से जुड़ी 13 FIR को आगे नहीं बढ़ाना चाहती।

छात्रों का आंदोलन कई शहरों तक पहुंचा था

बताया गया कि मामले की शुरुआत छात्रों के आंदोलन से हुई थी। इसके बाद आंदोलन का असर कई शहरों तक पहुंच गया। प्रदर्शनकारियों की ओर से कई मांगें उठाई गई थीं। आंदोलन की प्रमुख मांगों में तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी शामिल थी। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र और समर्थक सड़कों पर उतरे थे।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से 5 सितंबर को प्रस्तावित मार्च वापस लेने की घोषणा की गई। संगठन ने कोर्ट के आदेश और सरकार की ओर से दिए गए सकारात्मक भरोसे को देखते हुए यह फैसला लिया। कोर्ट ने भी संगठन के इस कदम को सकारात्मक बताया। इससे मामले में दोनों पक्षों के बीच टकराव कम होने और आगे की स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जगी है।

> कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्ति का इस्तेमाल इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि दोनों पक्षों की ओर से कोर्ट के सामने हुए समझौते और दिए गए आश्वासनों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से प्रदर्शन में शामिल लोगों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई। सरकार ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान आपराधिक रिकॉर्ड वाले 2,873 लोग वहां पहुंचे थे। हालांकि, ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट के निर्देश के अनुसार यदि इनमें से किसी व्यक्ति ने प्रदर्शन के दौरान मारपीट की या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी आपराधिक गतिविधि की है तो संबंधित मामले में कार्रवाई जारी रखी जा सकती है।

सीजेआई और कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता आमने-सामने

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। वह बेंच के सामने पेश हुए और संगठन की ओर से बयान पढ़ा। उन्होंने कहा कि सरकार के सकारात्मक भरोसे, न्यायिक स्वीकृति और कोर्ट के आदेश को देखते हुए संगठन ने 5 सितंबर को प्रस्तावित मार्च वापस लेने का फैसला किया है। सौरव दास के बयान के बाद CJI सूर्यकांत ने संगठन के इस कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि एक संस्था के रूप में कोर्ट इस सकारात्मक वातावरण के लिए आभारी है।

गोवा-दिल्ली फ्लाइट के इंजन में खराबी

उड़ान भरने के कुछ देर बाद 14 हजार फीट पर पता चला

तमसा संकेत, एजेंसी

गोवा से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 2102 को उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद एक इंजन में तकनीकी खराबी की सूचना मिली। इसके बाद विमान को वापस मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाया गया। फ्लाइट ने सुबह 9:16 बजे उड़ान भरी थी और 9:30 बजे सुरक्षित लैंडिंग की। Flightradar24 के डेटा के मुताबिक वापस मुड़ते समय विमान करीब 14 हजार फीट की ऊंचाई पर था। विमान में 229 यात्री सवार थे। इंडिगो ने बताया कि विमान की फिलहाल मेंटेनेंस जांच की जा रही है। सभी जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद ही विमान दोबारा उड़ान भरेगा। कंपनी ने कहा कि असुविधा को कम करने के लिए यात्रियों को खाने-पीने की चीजें उपलब्ध कराई गईं और उन्हें समय-समय पर जानकारी दी गई। यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है। चेन्नई एयरपोर्ट पर 12 अगस्त की देर रात एक इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। फ्लाइट कोलकाता से चेन्नई जा रही थी। फ्लाइट चेन्नई में लैंड करने वाली थी, तभी पायलट ने महसूस किया कि बायां इंजन फेल हो गया है।

मोदी की फिर अपील-जरूरत न हो तो सोना नहीं खरीदें

वैश्विक संकट में भारत की जीडीपी 7.8% दर से बढ़ी

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% रहने पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि यह उपलब्धि देशवासियों की इच्छाशक्ति, मेहनत और सामूहिक ताकत का नतीजा है। PM ने एक बार फिर लोगों से गैर-जरूरी सोने की खरीदारी से बचने की अपील की। उन्होंने कहा, 'अगर जरूरत न हो तो सोना नहीं खरीदना चाहिए।' इससे पहले 10 मई को भी PM ने देशवासियों से सोना नहीं खरीदने की अपील की थी। पीएम मोदी ने राहुल का नाम लिए बिना कहा- देश के अंदर कुछ लोग निराशा फैलाने और 'झूठ की गूंज' के सहारे माहौल खराब करने में लगे हैं। इन सभी चुनौतियों के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है।

>> (शेष पेज 06 पर)

फास्ट न्यूज

नाबालिग पत्नी से संबंध बनाना पॉक्सो के तहत अपराध

तिरुवनंतपुरम। केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को 17 साल की लड़की से रेप के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ केस रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक संबंध उसे कार्रवाई से नहीं बचा सकता। जस्टिस जोबिन सेबेस्टियन ने 19 अगस्त 2026 के आदेश में यह टिप्पणी की।

सुभाष चंद्रा केस में एनसीएलटी के आदेश पर रोक

नई दिल्ली। NCLT की 5-सदस्यीय बेंच ने मंगलवार को जी ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा के रीपेमेंट प्लान पर रोक लगा दी है। 25 अगस्त के आदेश में उनके 22,000 करोड़ से ज्यादा के बकाए कर्ज के बदले सिर्फ 6.25 करोड़ चुकाने के प्लान को मंजूरी दी गई थी कोर्ट ने सुभाष चंद्रा पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी किसी भी संपत्ति को बेचने या ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है। सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किया है।

यूपी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट- अब तक 13 की मौत

प्रयागराज/कौशांबी। यूपी में प्रयागराज-कौशांबी बॉर्डर पर अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। मंगलवार दोपहर मेडिकल कॉलेज में एक घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं, एक अन्य शव पोस्टमॉर्टम हाउस में रखा था। बुजुर्ग पिता ने उसकी पहचान अपने बेटे सुनील के रूप में की। दरअसल, सोमवार को सुनील का सिर्फ एक पैर मिला था।

खरगे ने चुनाव आयोग को बीजेपी बचाओ कमीशन कहा

बोले- जहां बीजेपी को फायदा होता है, वहां मतदाता जोड़ दिए जाते हैं

विरोध

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। नई दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आयोग निष्पक्ष चुनावों के संरक्षक की जगह 'सेव बीजेपी चेयर कमीशन' की तरह काम कर रहा है। खरगे ने आरोप लगाया कि बीजेपी 'वोट चोरी' के जरिए भारत के लोकतंत्र को खोखला करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह साजिश अब सामने आ गई है और लोग वोटों की चोरी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। खरगे ने हिंदी में किए X पोस्ट में आरोप लगाया कि बीजेपी जहां अपने फायदे के लिए वोट बढ़ाती है, वहीं जहां फायदा नहीं होता, वहां वोटों को बांट देती है। उन्होंने कहा- बीजेपी की 'वोट चोरी' के जरिए भारतीय लोकतंत्र को खोखला करने की साजिश सामने आ रही है। जहां बीजेपी को फायदा होता है, वहां मतदाता जोड़े जाते हैं और जहां फायदा नहीं होता, वहां वोट बांट दिए जाते हैं।" खरगे ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच अचानक 39 लाख मतदाता बढ़ गए थे। अब SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की ड्राफ्ट सूची से 2.07 करोड़ मतदाता बाहर हैं।

>> (शेष पेज 06 पर)

उनके साथ खड़े ईरानी राष्ट्रपति को भी नहीं दिखाया, एक्स पर एडिटेड फोटो शेयर की

पाकिस्तान ने एससीओ समिट की तस्वीर से मोदी को हटाया

विरोध

तमसा संकेत, एजेंसी

बिश्केक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की गई एक ग्रुप फोटो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, SCO समिट के दौरान ली गई ग्रुप फोटो को एडिट करके प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटा दी गई है। यह तस्वीर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में ली गई थी। इसमें सदस्य देशों के नेता एक मंच पर खड़े नजर आ रहे हैं। मूल तस्वीर में मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत 12 नेता दिखाई दे रहे हैं। वहीं, एडिटेड तस्वीर में सिर्फ 6 नेता दिख रहे हैं। मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी SCO समिट का ग्रुप फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें शहबाज शरीफ नजर आ रहे हैं।

>> (शेष पेज 06 पर)

पुतिन बोले- एससीओ अब दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की शुरुआत कुछ देशों के छोटे संगठन के तौर पर हुई थी, लेकिन अब यह दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन बन गया है। पुतिन के मुताबिक, SCO के सदस्य देशों में दुनिया की करीब आधी आबादी रहती है और ये देश दुनिया की कुल GDP के करीब एक-तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।

पुतिन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की याद दिलाई

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के 87 साल पूरे होने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसी वैश्विक उकसावे वाली घटनाएं नहीं होनी चाहिए, जो नए युद्ध को जन्म दें। पुतिन ने कहा कि देशों को मिलकर काम करना होगा, ताकि दुनिया में नए संघर्षों को भड़कने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा सहयोग और प्रयास इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगे।

जवाबदारी : क्या किसी की जवाबदेही तय होगी, ड्राइवर-कंडक्टर पर चलती बस में दुष्कर्म करने का आरोप

नाकामी पर कब तक पर्दा डालेंगे : राहुल

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। राहुल गांधी ने दिल्ली में 16 साल की नाबालिग से स्लीपर बस में गैंगरेप के मामले को लेकर केंद्र के साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 47 किमी चलती बस में लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी तक नहीं हुई। किसी को जवाबदारी लेनी होगी। दरअसल, सोमवार को दिल्ली में नाबालिग से चलती स्लीपर बस में गैंगरेप का मामला सामने आया था। पुलिस के मुताबिक, घटना 4 अगस्त की है, जिसकी जानकारी पुलिस ने 31 अगस्त को दी। बस के ड्राइवर-कंडक्टर को अरेस्ट कर लिया गया है। बस में लगे पर्दे सिर्फ उस घटना को छिपाने का जरिया नहीं थे, बल्कि ये सरकार की प्रशासनिक नाकामियों पर सालों से पड़े पर्दे को भी दिखाते हैं। राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य सरकारों से जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने सवाल किया कि आखिर कितनी महिलाओं और लड़कियों को ऐसी घटनाएं झेलनी पड़ेंगी, तब जाकर केंद्र और राज्य सरकारें व्यवस्था में सुधार करेंगी।

> *पुलिस के मुताबिक, पीड़ित यूपी के मैनपुरी की रहने वाली है। परिवार में झगड़ा होने पर बिना बताए नोएडा में कजिन के घर के लिए बस से निकली। मैनपुरी से नोएडा की दूरी 300 किमी से ज्यादा है। भारी बारिश और अंधेरे के कारण छात्रा गलती से परी चौक पर उतर गई थी। फिर यहां से नोएडा जाने के लिए वाहन का इंतजार करने लगी। इसी बीच वहां से एक खाली स्लीपर बस गुजरी। छात्रा ने बस को रुकने का इशारा किया।*

राहुल बोले- ये सरकार की नाकामी

राहुल गांधी ने मंगलवार को X पर पोस्ट कर कहा, दिल्ली महिलाओं के लिए असुरक्षित हो गई है। स्लीपर बस में हुई घटना की जानकारी दिल्ली और नोएडा पुलिस को भी नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि 2012 के निर्भया मामले के इतने साल बाद और महिलाओं के खिलाफ ऐसी कई घटनाओं के बावजूद स्लीपर बसों की जांच और निगरानी के नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा है।

बस करीब 47 किमी दौड़ती रही

पुलिस के मुताबिक पीड़ित ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर बस में बैठी। आरोपियों ने उसे कश्मीरी गेट पर छोड़ा। इस दौरान बस करीब 47 किमी दौड़ती रही। बस के शीशों पर पर्दे लगे थे। पुलिस ने बस ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी कब हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। पीड़ित उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की रहने वाली है और 11वीं की छात्रा है।

ममता बनर्जी की भतीजी फंदे से लटकी मिलीं

शिक्षक भर्ती घोटाले में चली गई थी नौकरी, 2 साल से डिप्रेशन में थीं

तमसा संकेत, एजेंसी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भतीजी ब्रिष्टी मुखर्जी मंगलवार को बीरभूम जिले के कुसुंबा गांव के घर में फंदे से लटकी मिलीं। ब्रिष्टि, ममता के चचेरे भाई और तृणमूल नेता निहार मुखर्जी की बेटी थीं। शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रिष्टि बोलपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थीं। शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आने के बाद 2024 में उनकी जॉब चली गई थी। इसके बाद से ही वे डिप्रेशन में थीं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल, 2024 को अवैध रूप से प्राप्त सभी 25,753 नौकरियां रद्द कर दी थीं। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो लोग लंबे समय से अवैध तरीके से काम कर रहे हैं, उन्हें ब्याज समेत सैलरी लौटानी होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2016 में स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट-2016 (SLCT) के जरिए सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती की थी।

>> (शेष पेज 06 पर)

परिवहन विभाग को जल्द मिलेगा लखनऊ के अहिमामऊ में अपना पहला डिटेंशन-डम्पिंग यार्ड

पी-4 और कल्ली यार्ड से शिफ्ट होंगे वाहन

सुविधा

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। राजधानी में जब्त वाहनों को रखने की वर्षों पुरानी समस्या का अब जल्द समाधान हो जाएगा। परिवहन विभाग के लिए अहिमामऊ में तैयार किया गया डिटेंशन/डम्पिंग यार्ड निर्माण का काम पूरा हो चुका है और अब तकनीकी समिति के निरीक्षण के बाद इसे परिवहन विभाग को हस्तांतरित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। करीब 2.55 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस यार्ड में एक साथ 136 हल्के वाहन, 15 भारी वाहन और 86 दोपहिया वाहन, यानी कुल 237 वाहन खड़े किए जा सकेंगे। विभाग ने इसे योगी सरकार के सड़क सुरक्षा से जुड़े विजन की ओर अच्छा व बड़ा कदम बताया है। अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) केडी सिंह गौर ने बताया कि यह व्यवस्था लखनऊ में परिवहन विभाग और प्रवर्तन टीमों की कार्रवाई के बाद जब्त या निरुद्ध होने वाले वाहनों को व्यवस्थित तरीके से रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अभी पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण कई बार कार्रवाई के बाद वाहनों को थानों व उपलब्ध खुले स्थानों में खड़ा करना पड़ता है। इससे थानों में जगह की समस्या के साथ-साथ सड़क किनारे या अन्य खुले स्थानों पर यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है।

उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त उत्तर के निर्देश पर लखनऊ में डिटेंशन यार्ड के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके बाद नगर आयुक्त लखनऊ से जमीन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। नगर निगम की ओर से ग्राम अहिमामऊ में 0.780 हेक्टेयर (83,958 स्क्वायर फीट) भूमि परिवहन विभाग द्वारा निरुद्ध वाहनों की पार्किंग के लिए अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई गई। आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2026-27 में लखनऊ के प्रवर्तन दलों ने कुल 5,628 वाहनों का चालान किया है, जबकि 491 वाहनों को निरुद्ध किया गया। हालांकि वर्तमान में प्रवर्तन अधिकारियों के पास वाहनों को निरुद्ध करने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है।

पी-4 पार्किंग और कल्ली यार्ड से भी होगी व्यवस्था बेहतर

फिलहाल पी-4 पार्किंग और कल्ली यार्ड पीजीआई में वाहन खड़े किए जाते हैं। नए अहिमामऊ डम्पिंग यार्ड के उपलब्ध होने से इन स्थानों पर खड़े वाहनों को भी आवश्यकता के अनुसार नए यार्ड में शिफ्ट किया जा सकेगा। इससे अलग-अलग स्थानों पर जब्त वाहनों के बिखरे रहने की समस्या कम होगी और वाहनों के लिए एक केंद्रीकृत व्यवस्था विकसित होगी।

2.55 करोड़ की लागत से हुआ तैयार, 237 वाहन रखने की क्षमता, जल्द मिलेगा हैंडओवर

थानों और खुले स्थानों पर घटेगा दबाव

लखनऊ में जब्त वाहनों को मिलेगा स्थायी ठिकाना, 136 हल्के और 15 भारी वाहन हो सकेंगे खड़े

जाम से लेकर सड़क सुरक्षा तक राहत, सीएम योगी के सड़क सुरक्षा विजन की दिशा में लखनऊ को बड़ी सुविधा

2.55 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ यार्ड

इसके बाद परिवहन आयुक्त के निर्देश पर मुख्य भवन, गार्ड रूम और बाउंड्रीवाल आदि के निर्माण के लिए 2.55 करोड़ रुपये से अधिक स्वीकृत किए गए। 21 अगस्त 2026 को संबंधित कार्यदायी संस्था ने बताया कि डिटेंशन यार्ड/डम्पिंग यार्ड से संबंधित सभी निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। अब कार्य पूर्ण होने के बाद इसे परिवहन विभाग को हस्तांतरित किया जाना है। हस्तांतरण से पहले तकनीकी समिति द्वारा यार्ड का निरीक्षण किया जाएगा। इस समिति में लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सिंचाई विभाग आदि के अभियंताओं को शामिल किया गया है। समिति स्थल का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद हस्तांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

राहुल गांधी पर एफआईआर विरोध में सांसद धरने पर बैठे

लखनऊ पुलिस ने जबरदस्ती उठाकर हिरासत में लिया

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में मंगलवार को कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के शुद्धिकरण के मामले को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया। बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज स्थित GPO गांधी प्रतिमा पर करीब 45 मिनट तक नारेबाजी और हंगामा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई।

तनुज पुनिया ने कहा कि संविधान को ताक पर रखकर कार्रवाई हो रही है। राहुल गांधी पर दर्ज FIR वापस होने तक कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान तनुज पुनिया समेत कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर ईको गार्डन भेज दिया।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गलत FIR वापस

लो-भाजपा सरकार होश में आओ जैसे नारे लगाए। तनुज पुनिया ने कहा कि संविधान को ताक पर रखकर कार्रवाई हो रही है। किसी के खिलाफ भी कार्रवाई भावना के आधार पर नहीं, बल्कि संविधान के अनुसार होनी चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी पर FIR हुई है, कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। राहुल गांधी ने दलित अपमान का मुद्दा उठाया था और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तनुज पुनिया ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में कार्यक्रम किया था।

फास्ट न्यूज

लोगों के प्रदर्शन के बाद लखनऊ नगर निगम एक्टिव

दुबग्गा । लखनऊ में बुद्धेश्वर के बादल खेड़ा में जलभराव के खिलाफ लोगों के प्रदर्शन के बाद नगर निगम एक्टिव हो गया है। प्रदर्शन के अगले ही दिन मंगलवार को नगर निगम की टीम पोकलैंड मशीन और पंप लेकर पहुंच गई। पोकलैंड मशीन से रास्तों और नालों में जमा सिल्ट हटाने और गंदे पानी की निकासी शुरू कर दी। सफाई निरीक्षक ने बताया कि 1 बड़ी और 2 छोटी पोकलैंड मशीन के साथ 3 पंप लगाए गए हैं।

मालिक की हत्या के लिए 40 लाख में किया सौदा

लखनऊ। लखनऊ में महाराणा प्रताप चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रापर्टी डीलर धीरेंद्र प्रताप सिंह (45) की अपहरण के बाद हत्या के मामले में साजिश की परतें खुलने लगी हैं। पुलिस की छानबीन में सामने आया है कि धीरेंद्र की हत्या के लिए ड्राइवर रवि तिवारी को साजिशकर्ताओं ने दो लाख रुपए देकर अमीनाबाद से असलहा खरीदवाया था। रवि को एक लाख रुपए खर्चे के लिए दिए थे। यानी हत्या से पहले उसे तीन लाख रुपए मिले थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हत्या के बाद रवि को 40 लाख रुपए या उन्नाव के बांगरमऊ में दो दुकानें और 10 लाख रुपए नकद देने का सौदा तय हुआ था।

एलएसए की सफाई व्यवस्था पर भाजपा पार्षद नाराज

लखनऊ । LSA की सफाई व्यवस्था से नाराज भाजपा पार्षदों ने महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी से मुलाकात की।

पार्षदों ने आरोप लगाया कि कंपनी सफाई में लापरवाही बरत रही है और कर्मचारियों को भुगतान भी नहीं कर रही। पार्षदों ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो दोबारा धरना-प्रदर्शन करेंगे।

खरीफ-2026 में फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 10 सितंबर तक बढ़ी

योगी सरकार के अनुरोध पर केंद्र ने बढ़ाई समयसीमा

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किसानों के हित में राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने खरीफ 2026 मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं चयनित जनपदों में संचालित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत ऋणी कृषकों के फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 10 सितंबर 2026 कर दी है। प्रदेश के प्रदेश सरकार द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने प्रदेश के सभी जनपदों के ऋणी कृषकों को राहत दी है। कृषि मंत्री ने प्रदेश के सभी पात्र किसानों से आह्वान किया है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपनी खेती को प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रतिकूल मौसमीय जोखिमों से

सुरक्षित रखें। प्रदेश के सभी जनपदों में प्राकृतिक आपदा एवं प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण फसल नुकसान से किसानों की आय को स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजनाएं संचालित की जा रही हैं। शासन द्वारा वर्ष 2026-27 में भी इन योजनाओं को पूर्ववत लागू किया गया है। तिथि विस्तार की सूचना प्रदेश के सभी बैंकों और संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है, जिससे अधिक से अधिक पात्र ऋणी कृषकों को आच्छादित कर उन्हें आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके। प्रदेश में फसल बीमा योजना के जरिए किसानों को व्यापक आर्थिक संबल मिल रहा है। वर्ष 2017-18 से 2025-26 तक प्रदेश के 69.22 लाख लाभार्थी किसानों को कुल 6,119.93 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दी जा चुकी है। खरीफ 2025 में 20.63 लाख बीमित कृषकों में से 7.27 लाख किसानों को 808.56 करोड़ रुपये तथा रबी 2025-26 में 1.67 लाख किसानों को 134.60 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है। इस संबंध में सभी पात्र ऋणी किसानों से बिना विलंब अपनी बैंक शाखा से संपर्क कर 10 सितंबर तक बीमा कराने की अपील की गई है।

खाने की गुणवत्ता जांच से लेकर साफ-सफाई तक विभागीय स्तर पर होती है निगरानी

नौनिहालों की सेहत को योगी सरकार का पोषण कवच

- आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिल रहा पौष्टिक आहार
- यूपी में हॉट कुक्ड मील योजना से आंगनबाड़ी केंद्रों में बदली पोषण व्यवस्था
- 32.88 लाख बच्चों को नियमित मिल रहा गर्म व पौष्टिक भोजन

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और मजबूत पोषण की दिशा में योगी सरकार की ओर से लगातार किए जा रहे प्रयासों का असर आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिखाई दे रहा है। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण-2.0 की गाइडलाइन के तहत

योगी सरकार ने बच्चों के भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर भी स्पष्ट मानक तय किए हैं। कोटेदार से मिलने वाला खाद्यान्न उत्तम गुणवत्ता का होना अनिवार्य है।

संचालित हॉट कुक्ड मील योजना के जरिए 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को नियमित रूप से ताजा, गर्म और पौष्टिक पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। यूपी में करीब 1.45 लाख को-लोकेटेड और 0.44 लाख नॉन को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले लगभग 32.88 लाख बच्चे नियमित लाभान्वित हो रहे हैं। भोजन तैयार करने से पहले अनाज की अच्छी तरह सफाई और हरी सब्जियों को दो से तीन बार पानी से धोने की व्यवस्था है। इससे बच्चों को स्वच्छ और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। भोजन बच्चों को परोसने से पहले कम से कम दो वयस्क व्यक्तियों जैसे शिक्षक, रसोइया या माता समिति के सदस्य द्वारा रोस्टर के आधार पर भोजन की जांच की जाती है। इसमें भोजन के स्वाद और गुणवत्ता को परखा जाता है। विभागीय व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों तक पहुंचने वाला भोजन पौष्टिक होने के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित भी हो। अपर मुख्य सचिव (महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग) लीना जौहरी ने बताया कि इसके जरिए नियमित 32.88 लाख बच्चों को गर्म और पौष्टिक आहार मिल रहा है। प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न से तैयार भोजन दिया जाता है।

साप्ताहिक मेन्यू में पौष्टिक व विविध भोजन

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के साप्ताहिक मेन्यू के अनुसार, बच्चों को अलग-अलग दिनों में रोटी-सब्जी, चावल-दाल, मौसमी सब्जियों से तैयार तहरी और अन्य पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। योगी सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से छोटे बच्चों को नियमित गर्म भोजन उपलब्ध कराकर सरकार एक ओर उनके पोषण स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर कम उम्र से ही संतुलित आहार की आदत विकसित करने की दिशा में भी काम कर रही है।

योगी सरकार सरकारी संस्थानों में हथकरघा उत्पादों की खरीद को देगी बढ़ावा

समयबद्ध आपूर्ति के लिए नोडल अधिकारी किए जाएंगे नामित

- अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बेडशीट व गॉज बैंडेज की आपूर्ति को लेकर मंत्री राकेश सचान ने की समीक्षा
- बुनकरों की युवा पीढ़ी को परंपरागत व्यवसाय से जोड़ने का प्रयास

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश की योगी सरकार हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग को प्रोत्साहन देने तथा प्रदेश के बुनकरों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए

सरकारी संस्थानों में स्थानीय स्तर पर निर्मित हथकरघा उत्पादों की खरीद को बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में मंगलवार को विधान भवन स्थित कक्ष संख्या-80 में खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य सरकारी विभागों तथा शासकीय उपक्रमों में प्रयुक्त होने वाले बेडशीट एवं गॉज बैंडेज की खरीद और आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंत्री राकेश सचान ने कहा कि प्रदेश के बुनकरों को सरकारी खरीद का बाजार उपलब्ध कराना योगी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

बुनकरों को सरकारी खरीद के माध्यम से मिलेगा स्थायी बाजार और रोजगार

प्रदेश में लगभग 2,13,107 बुनकर कार्यरत

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में लगभग 2,13,107 बुनकर कार्यरत हैं। बेडशीट तथा गॉज बैंडेज सहित विभिन्न वस्त्रों का उत्पादन प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में बुनकरों द्वारा किया जा रहा है। सरकारी खरीद में इन उत्पादों को प्राथमिकता मिलने से बुनकरों के उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जा सकेगा और परंपरागत बुनकरी व्यवसाय से नई पीढ़ी को जोड़ने में भी मदद मिलेगी।

समीक्षा बैठक में प्रस्तावित व्यवस्था के तहत सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आवश्यकतानुसार बेडशीट, तकिया कवर तथा गॉज बैंडेज क्लॉथ की आपूर्ति उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड के माध्यम से सुनिश्चित किए जाने पर चर्चा हुई। इसके लिए प्रदेश के बुनकर सहकारी समितियों एवं बुनकरों से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कराया जाएगा। संबंधित चिकित्सा संस्थानों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप मांग एवं क्रय आदेश समय से जारी किए जाने की व्यवस्था विकसित करने पर भी विचार किया गया।

राजधानी में 68,500 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का हंगामा

शिक्षा मंत्री का आवास घेरा, बोले- जल्द की जाए नियुक्ति

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ । लखनऊ में मंगलवार को 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। नियुक्ति की मांग को लेकर करीब एक घंटे तक नारेबाजी और हंगामा किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। प्रदर्शन में दिव्यांग अभ्यर्थी भी शामिल हुए।

प्रदर्शनकारियों ने ऐसी क्या मजबूरी है-आरक्षण की चोरी है और 'पिछड़ा आयोग ने माना है-आरक्षण घोटाला है जैसे नारे लगाए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाने का प्रयास किया। पुलिस सभी अभ्यर्थियों को टांगकर वहां से ले गई। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, वर्ष 2018 में 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती निकाली गई थी।

इसमें दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% की छूट का प्रावधान था। आरोप है कि इन चारों श्रेणियों के अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिला और सामान्य अभ्यर्थियों के साथ ही परिणाम जारी कर दिया गया। अभ्यर्थियों की मांग है कि भर्ती परीक्षा के पासिंग मार्क्स में 5% की छूट दी जाए। उनका कहना है कि 150 पूर्णांक वाली परीक्षा में 60 अंक यानी 40% अंक पर परिणाम संशोधित कर नई चयन सूची जारी की जाए।

आह्वान : 2027 चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं को संदेश

'एक भी वोट न छूटे, भाजपा की साजिशों से रहें सावधान'

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने का आह्वान किया। मंगलवार को सपा प्रदेश मुख्यालय पर विभिन्न जिलों से पहुंचे नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर 2024 के लोकसभा चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि समाजवादी समर्थकों का एक भी वोट कम न होने पाए और कोई वोट

छूटने न पाए। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। कार्यकर्ताओं को पूरी सजगता के साथ चुनाव की तैयारी करनी होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की साजिशों से सावधान रहने की जरूरत है और इस बार किसी तरह का धोखा नहीं होना चाहिए। सपा अध्यक्ष ने भाजपा पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र के खिलाफ है और लोकतंत्र, संविधान तथा आरक्षण के लिए खतरा है। उन्होंने भाजपा सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान विरोधी भी बताया।

अखिलेश यादव ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि लखनऊ के कैंसर संस्थान की व्यवस्था खराब हो गई है और सरकार इसे ठीक से नहीं चला पा रही है। जिलों के मेडिकल कॉलेजों में भी इलाज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने का आरोप उन्होंने लगाया।

'भाजपा के कुशासन से जनता त्रस्त'

सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कुशासन, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार से जनता परेशान हो चुकी है। जनता भाजपा को सत्ता से हटाना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में हर स्तर पर भेदभाव हो रहा है। उनके मुताबिक भाजपा के अन्यायी शासन के खिलाफ पीडीए एकजुट है और पीडीए की एकजुटता से भाजपा घबराई हुई है।

पीडीए को बताया 'प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट' का मॉडल

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का पीडीए प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट का है। इसमें प्रेम, दया और अपनापन है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सभी वर्गों को साथ जोड़ने और हर व्यक्ति का सम्मान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि बूथों को मजबूत करें और जनता तक समाजवादी पार्टी की योजनाओं और नीतियों को पहुंचाएं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सभी के साथ प्रेम और अपनत्व का व्यवहार करते हुए संगठन को मजबूत करने को कहा।

'हौसलों की उड़ान 2026' में बोले समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण

खुन खुन जी गर्ल्स पी.जी. कॉलेज में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ । प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने मंगलवार को लखनऊ स्थित खुन खुन जी गर्ल्स पी.जी. कॉलेज में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 'हौसलों की उड़ान 2026' में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कॉलेज की छात्राओं से सीधा संवाद किया और शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों में उनकी उत्कृष्ट भागीदारी की सराहना की।

समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री असीम अरुण ने कहा, ''हमारी बेटियों में अपार प्रतिभा और आत्मविश्वास है। पढ़ाई के साथ-साथ खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों में उनकी रुचि यह साबित करती है कि वे हर क्षेत्र में नए

कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तैयार हैं। बेटियों के इस हौसले और प्रतिभा को मैं सलाम करता हूँ।'' उन्होंने पारंपरिक खेलों एवं सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से छात्राओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कॉलेज प्रशासन के प्रयासों का विशेष धन्यवाद व्यक्त किया।

कॉलेज में संचालित ''मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना'' का लाभ लेते हुए 80 बच्चों का विभिन्न परीक्षाओं में चयन हो चुका है। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहीं छात्राओं को और अधिक सशक्त बनाने तथा डिजिटल संसाधनों से जोड़ने के लिए जल्द ही एक आधुनिक कंप्यूटर लैब की शुरुआत की जाएगी। इस लैब के बनने से अभ्युदय कोचिंग के विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट और डिजिटल रिसर्च में सीधी मदद मिलेगी।

गंगा एक्सप्रेसवे धंसा, शॉल डालकर छिपाया

उन्नाव में करीब 7 फीट गहरा गड्ढा हुआ, बैरिकेडिंग करके मरम्मत शुरू की

लापरवाही

तमसा संकेत, एजेंसी

उन्नाव। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे की सड़क को लेकर लापरवाही का मामला सामने आया है। बसीरतगंज टोल प्लाजा के पास प्रयागराज जाने वाली लेन पर करीब 7 फीट गहरा गड्ढा हो गया। सोमवार को सामने आए इस गड्ढे का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जिसके बाद एक्सप्रेसवे की सुरक्षा और निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे। हैरानी की बात यह रही कि गड्ढे को तत्काल भरने के बजाय उसे छिपाने के लिए उसके ऊपर शॉल डाल दी गई। इसके बाद आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई, ताकि वाहन चालक उस हिस्से में न पहुंच सकें। मामले की जानकारी मिलने के बाद मंगलवार को एक्सप्रेसवे का मेंटेनेंस संभाल रही कंपनी ने मरम्मत का काम शुरू किया। बसीरतगंज टोल प्लाजा के पास प्रयागराज की ओर जाने वाली लेन में अचानक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि इसकी गहराई करीब सात फीट थी। सड़क के बीच बने इस गड्ढे से तेज रफ्तार वाहनों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। गड्ढे को ढकने के लिए उसके ऊपर शॉल डाल दी गई और आसपास बैरिकेड लगाकर रास्ते को सुरक्षित करने की कोशिश की गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। इसके बाद संबंधित मेंटेनेंस कंपनी ने मंगलवार को मौके पर पहुंचकर मरम्मत का काम शुरू किया।

66 पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजर आरएस मिश्रा ने बताया- टोल प्लाजा के पास से हाईटेंशन बिजली की लाइन गुजर रही है। नियमों के मुताबिक सड़क और बिजली के तारों के बीच 14 मीटर की दूरी रखना जरूरी था। इसलिए टोल प्लाजा को ज्यादा ऊंचा नहीं बनाया जा सका।

17 अगस्त को भी बह गया था सड़क का हिस्सा

गंगा एक्सप्रेसवे पर इस तरह की समस्या पहली बार सामने नहीं आई है। इससे पहले 17 अगस्त को सोनिक गांव के पास मिट्टी कटने के कारण एक्सप्रेसवे के किनारे करीब 200 मीटर सड़क का हिस्सा बह गया था। बारिश के कारण मिट्टी कटने से सड़क के किनारे का हिस्सा प्रभावित हुआ था। इसके बाद मरम्मत का काम शुरू किया गया और करीब दो दिन में सड़क को दुरुस्त किया गया। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं के बाद एक्सप्रेसवे की निर्माण गुणवत्ता, जल निकासी व्यवस्था और सड़क के रखरखाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

गंगा एक्सप्रेस-वे पर हुए गड्ढे को इस तरह से शॉल से ढका गया है। गड्ढे पर शॉल डालने के बाद अगल-बगल बैरियर लगा दिए गए हैं।

मरम्मत करके सड़क ठीक कर दी गई

उन्होंने आगे बताया कि मरम्मत करके सड़क ठीक कर दी गई है। आगे फिर कभी पानी न भरे, इसके लिए टोल के किनारे एक सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए टीमों को अलर्ट पर रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मरम्मत का काम किया जा सके।

हरदोई में बारिश से कच्ची दीवार ढही

मलबे में दबकर किसान की मौत, रात दो बजे मरभराकर गिरी

तमसा संकेत, एजेंसी

हरदोई। हरदोई जिले के बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के पिपरी गांव में सोमवार देर रात बारिश के कारण एक कच्ची दीवार ढह गई। मलबे में दबकर 70 वर्षीय किसान हरिपाल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सोमवार आधी रात के बाद 2 बजे की है। मंगलवार की दोपहर 1:30 बजे शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पिपरी गांव निवासी हरिपाल पुत्र शंकर पेशे से किसान थे। उनके परिवार में पत्नी कैलाशा, पांच बेटे (सतीश, अनिल, रजनीश, मधुरेश, विपिन) और दो विवाहित बेटियां हैं। सोमवार रात हरिपाल अपने घर के बगल में बने अहाते में सो रहे थे। इसी दौरान देर रात हुई बारिश के कारण एक पुरानी और जर्जर कच्ची दीवार अचानक उन पर गिर गई। दीवार गिरने की आवाज सुनकर परिजन बाहर भागे। उन्होंने पड़ोसियों की मदद से तुरंत मलबा हटाना शुरू किया और यूपी-112 पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ग्रामीणों के सहयोग से हरिपाल को मलबे से बाहर निकालने में सफल रही, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। हादसे की सूचना पर संबंधित क्षेत्र के लेखपाल ने गांव पहुंचकर मामले की जांच की। प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि दीवार काफी पुरानी और जर्जर थी।

फास्ट न्यूज

शादी टूटने से आहत युवक ने की आत्महत्या

उन्नाव। उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र के नगवा गांव में सोमवार रात एक 21 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी शादी तय थी, लेकिन बारात जाने से दो दिन पहले मंगेतर ने किसी अन्य युवक से शादी कर ली थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की पहचान नगवा निवासी 21 वर्षीय अनूप उर्फ भोला पुत्र नेकपाल के रूप में हुई है। वह एक स्थानीय फैक्ट्री में मजदूरी करता था।

हरदोई में महिला ने किया सुसाइड

हरदोई। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में 24 वर्षीय विवाहिता आकांक्षा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना सोमवार रात करीब 11 बजे बबक्कखरपुर मजरा फरिगाहना में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। फॉरेंसिक टीम ने जरूरी नमूने जुटाए। पिता ने मृतका के पति पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार की दोपहर करीब 2:30 बजे शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

2 बुजुर्ग महिलाओं में स्वाइन फ्लू की पुष्टि

उन्नाव। उन्नाव में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सोमवार रात आई जांच रिपोर्ट में गंजमुरादाबाद और बांगरमऊ क्षेत्र की दो बुजुर्ग महिलाओं में संक्रमण की पुष्टि हुई है। दोनों की उम्र 70 और 75 वर्ष है और गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजनों ने उन्हें लखनऊ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। स्वास्थ्य विभाग को जानकारी मिलने के बाद दोनों क्षेत्रों में टीमें भेजी गईं।

दो अलग-अलग हादसों में दंपती और बच्चों समेत 6 घायल

बारिश से दीवारें ढहीं

तमसा संकेत, एजेंसी

हरदोई। हरदोई में रात भर हुई मूसलाधार बारिश के कारण अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दीवारें ढहने से दो हादसों में दंपती व बच्चों समेत कुल छह लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया। एक हादसा मंगलवार सुबह 4 बजे और दूसरा 5 बजे हुआ। पहला हादसा लोनार कोतवाली क्षेत्र के बावन कस्बे के मोहल्ला बीरमपट्टी में हुआ। यहां सीमेंट की दुकान पर काम करने वाले रामकिशोर (47) का कच्चा मकान था, जिसमें कच्ची दीवारों के सहारे छप्पर पड़ा हुआ था। सोमवार रात रामकिशोर अपनी पत्नी रेखा (45), पुत्री गुंजन (13) और पुष्पा (7) के साथ छप्पर के नीचे सो रहे थे। मंगलवार सुबह करीब 4 बजे लगातार हो रही बारिश से कच्ची दीवार अचानक गिर गई, जिससे चारों लोग मलबे में दब गए। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने सभी को बाहर निकालकर सीएचसी पहुंचाया।

दूसरी घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के सधई बेहटा गांव की है। ई-रिक्शा चालक मुन्ना (50) के मकान में कमरे के आगे पक्की ईंटों के सहारे टिनशेड पड़ा था, लेकिन ईंटों की जुड़ाई मसाले से नहीं की गई थी। मंगलवार सुबह करीब 5 बजे बारिश की नमी के कारण ईंटें अचानक गिर पड़ीं, जिसकी चपेट में आकर मुन्ना और उनकी पत्नी खैरुन्निसा (45) दब गए। परिजनों ने दोनों को मलबे से निकाला। गंभीर रूप से घायल खैरुन्निसा को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जबकि मुन्ना को मामूली चोटें आई हैं। घटना के बाद बीरमपट्टी मोहल्ले में लेखपाल शशिकांत ने पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया और रिपोर्ट तैयार की।

शिक्षक की पिटाई से घायल-छात्रा की इलाज के दौरान मौत

हरदोई। हरदोई में शिक्षक की पिटाई से घायल 13 वर्षीय छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्रा के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की हालत स्कूल में एक क्लासमेट और शिक्षकों की पिटाई के बाद बिगड़ी थी। खंड शिक्षाधिकारी ने इस मामले में दो आरोपी शिक्षकों को निलंबित कर दिया। एएसपी बोले- जल्द गिरफ्तारी कर होगी। पूरा मामला जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर पचदेवरा थाना क्षेत्र के सहुआपुर गांव का है। सहुआपुर निवासी उमेश दीक्षित की बेटी क्षमा (13) गांव के संविलियन स्कूल में पढ़ती थी। 20 अगस्त को विद्यालय में परीक्षा के दौरान क्षमा की एक अन्य छात्रा से कहासुनी हो गई थी। इसके बाद उस छात्रा ने क्षमा के साथ मारपीट की। जब क्षमा इसकी शिकायत लेकर शिक्षकों के पास पहुंची, तो आरोप है कि शिक्षकों ने भी उससे मारपीट की और उसके दोनों हाथ मरोड़ दिए, जिससे वह घायल हो गई।

हरदोई में भाजपा की बैठक

सत्यापन, डिजिटल रिपोर्टिंग से संगठन को मिलेगी नई धार

तमसा संकेत, एजेंसी

हरदोई। हरदोई में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आगामी चुनावी वर्ष की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। यह बैठक मंगलवार दोपहर 1 बजे हुई, जिसमें मंडल कार्यसमिति सत्यापन और प्रवास योजना पर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने प्रदेश नेतृत्व के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संगठन को सशक्त बनाने के लिए मंडल प्रवासी, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी और सभी पदाधिकारियों को आपसी समन्वय से काम करना होगा। चुनावी वर्ष को देखते हुए बूथ स्तर तक संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और कमियों को दूर करने पर जोर दिया गया। इस दौरान प्रदेश द्वारा निर्धारित योजना के तहत समयबद्ध कार्य करने का संकल्प लिया गया। इसमें मंडल कार्यसमिति, शक्ति केंद्र संयोजकों और बूथ समितियों का अनिवार्य सत्यापन शामिल है। मंडल प्रवास के कार्यों को भी तय सीमा के भीतर पूरा करने पर गहन चर्चा हुई। सत्यापन कार्य की विस्तृत रिपोर्ट डिजिटल और सामान्य दोनों माध्यमों से भेजने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। यह सुनिश्चित करेगा कि संगठन की प्रगति और जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों की सटीक जानकारी उपलब्ध हो। बैठक में मंच पर पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीकृष्ण शास्त्री, पूर्व जिलाध्यक्ष रामबाहादुर सिंह, डीसीबी चेयरमैन अशोक सिंह, जिलामंत्री एवं अभियान संयोजक सत्यम शुक्ला, जिला मंत्री नीरज राजपूत और रितेश गुप्ता मौजूद रहे। इनके अतिरिक्त, जिला महामंत्री अनुराग मिश्रा, सतेंद्र राजपूत, जिला उपाध्यक्ष प्रीतेश दीक्षित, आकाश सिंह, सौरभ सिंह, संदीप सिंह, महेंद्र सोनी, अजय शुक्ला, जिला मंत्री दीपा विश्वास, अमरेंद्र अर्कवंशी, जिला मीडिया प्रभारी अतुल सिंह चाऊंपुर, कार्यालय मंत्री आजाद भदौरिया, पूर्व जिला उपाध्यक्ष सिद्धप्रताप मौर्य, संजय सिंह गुड्डू, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष विश्वराज सिंह, सह कार्यालय मंत्री आशुतोष आजाद, सह कोषाध्यक्ष कपिल मोहन गुप्ता, पूर्व जिला मंत्री अविनाश पांडेय, सुभाष पांडेय सहित सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक का समापन बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने के संकल्प के साथ हुआ, जिससे आगामी चुनावों के लिए संगठन की तैयारियों को गति मिल सके।

कतुरी खुर्द-हजरतापुर मार्ग पर जलभराव

हल्की बारिश से ग्रामीण परेशान, आवागमन में बाधा

तमसा संकेत, एजेंसी

बाराबंकी। बाराबंकी के निंदूरा विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कतुरी खुर्द से हजरतापुर गुलराही गांव को जोड़ने वाले मार्ग पर हल्की बारिश होते ही जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सड़क पर पानी जमा होने से ग्रामीणों और राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, मार्ग पर जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण बारिश का पानी सड़क पर ही जमा हो जाता है। इससे सड़क पर जगह-जगह कीचड़ हो जाता है, जिससे दोपहिया वाहन चालकों और पैदल चलने वालों के फिसलने का खतरा बना रहता है। इस जलभराव के कारण स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और स्थानीय लोगों को भी आने-जाने में दिक्कत होती है। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के दौरान मार्ग की स्थिति और भी खराब हो जाती है, क्योंकि पानी भरने से सड़क के गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से मार्ग की जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने और सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि बारिश के दिनों में आवागमन सुचारु रूप से हो सके। वहीं, प्रधान प्रतिनिधि परवेज अहमद ने आश्वासन दिया है कि जल निकासी की व्यवस्था जल्द ही की जाएगी।

बाराबंकी में सांड से टकराई बाइक, एक की मौत

बाराबंकी। बाराबंकी में आवारा पशुओं के कारण एक बार फिर सड़क हादसा हो गया। मंगलवार सुबह करीब 8 बजे लोनीकटरा थाना क्षेत्र के छबील गांव के पास यह घटना हुई। हैदरगढ़ से लखनऊ की ओर जा रही एक बाइक अचानक सड़क पर आई गाय से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। छबील चौकी प्रभारी अभय गुप्ता पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने बिना देरी किए डायल-108 एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं, दूसरे युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि हादसे में जान गंवाने वाले और घायल युवक दोनों कानपुर के निवासी हैं। पुलिस ने मृतकों और घायलों के परिजनों को सूचित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

दही चौकी कंपनी में कर्मचारी की करंट से मौत

सैंपल देखने के दौरान हादसा, 15-20 साल से थे कार्यरत

तमसा संकेत, एजेंसी

उन्नाव। उन्नाव के दही चौकी औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कंपनी में मंगलवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। यहां सैंपल देखने पहुंचे एक कर्मचारी की बिजली के करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद कंपनी में अफरा-तफरी मच गई। साथी कर्मचारियों ने उन्हें बचाने और इलाज के लिए ले जाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि हादसा जिस समय हुआ, उस दौरान आसपास मौजूद अन्य कर्मचारियों को तत्काल इसकी जानकारी नहीं हो सकी। कुछ समय बाद जब साथी कर्मचारियों को घटना का पता चला तो उन्होंने ओम प्रकाश को बचाने का प्रयास किया। कर्मचारियों ने उन्हें उपचार के लिए ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद कंपनी में मौजूद कर्मचारियों के बीच शोक की स्थिति बन गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम कंपनी पहुंची।

परिजनों को दी गई सूचना, घर में मचा कोहराम

हादसे की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों को सूचना दी गई। ओम प्रकाश की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजन कंपनी पहुंचे और शव को देखकर उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सहकर्मियों ने बताया कि ओम प्रकाश लंबे समय से कंपनी से जुड़े हुए थे और अपने काम को लेकर अनुभवी कर्मचारी थे। उनकी अचानक मौत से साथी कर्मचारी भी स्तब्ध हैं।

भोजन के बाद सैंपल देखने पहुंचे थे कर्मचारी

मृतक की पहचान दरियाई खेड़ा निवासी ओम प्रकाश के रूप में हुई है। उनके साथी कर्मचारी बृजभान ने बताया कि ओम प्रकाश पिछले करीब 15 से 20 वर्षों से कंपनी में काम कर रहे थे। उन्हें कंपनी के काम का काफी अनुभव था। मंगलवार को दोपहर में भोजन करने के बाद ओम प्रकाश कंपनी में सैंपल देखने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान वह बिजली के करंट की चपेट में आ गए और अचानक जमीन पर गिर पड़े।

योगदान : उन्नाव की शिक्षिका का 20 साल की मेहनत के बाद चयन

शिक्षिका प्रीति भारती को राज्य शिक्षक पुरस्कार

तमसा संकेत, एजेंसी

उन्नाव। उन्नाव के प्राथमिक विद्यालय नेवलगंज, हसनगंज की शिक्षिका प्रीति भारती का चयन वर्ष 2025 के राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए हुआ है। उन्हें शैक्षिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। 5 सितंबर को लखनऊ में आयोजित समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री चयनित शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। शासन ने सोमवार को 61 जिलों के चयनित शिक्षकों की सूची जारी की, जिसमें उन्नाव से प्रीति भारती का नाम शामिल है। इस बार जिले से राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए उन्होंने ही आवेदन किया था। कड़े मानकों के बीच उनका चयन जिले के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। सूची में अपना नाम देखकर प्रीति भारती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिवार, शिक्षक साथियों और परिचितों को जानकारी मिलते ही बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। प्रीति भारती के अनुसार, यह सम्मान उनके करीब 20 वर्षों के शिक्षक कार्यकाल में बच्चों की शिक्षा के लिए की गई मेहनत, ईमानदारी और लगातार किए गए नए प्रयोगों का परिणाम है। प्रीति भारती ने पारंपरिक शिक्षण के साथ तकनीक और रचनात्मकता को जोड़कर बच्चों के लिए पढ़ाई को आसान और रुचिकर बनाने पर जोर दिया। आईसीटी के क्षेत्र में उनके कार्यों को देखते हुए राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, प्रयागराज की ओर से उन्हें पांच दिवसीय कार्यशाला के लिए आईआईटी गांधीनगर भेजा गया था। वहां उन्होंने आधुनिक शिक्षण तकनीकों और डिजिटल माध्यमों के प्रयोग की जानकारी हासिल की। वर्ष 2021-22 और 2022-23 में लगातार दो वर्षों तक उनका चयन राज्य स्तरीय आईसीटी प्रतियोगिता के लिए हुआ। इसके अलावा राज्य स्तरीय टीएलएम प्रतियोगिता में भी उनका चयन हो चुका है। एससीईआरटी के पीएम ई-विद्या चैनल नंबर 175 पर उनके वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। गणित और विज्ञान की लाइव कक्षाओं के लिए भी उनके शिक्षण वीडियो प्रसारित होते हैं। इसके अलावा आईजीओटी-कर्मयोगी के माध्यम से कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए भी उनकी रिकॉर्डिंग कराई गई है।

जिले की कई शिक्षिकाओं को पहले मिल चुका सम्मान

उन्नाव से इससे पहले भी कई शिक्षिकाओं को राज्य अध्यापक पुरस्कार मिल चुका है। वर्ष 2018 में डॉ. रचना सिंह, 2019 में रश्मि तिवारी, 2021 में सविता सैनी, 2022 में प्रज्ञा त्रिवेदी और 2024 में सेविना दीक्षित को राज्य अध्यापक पुरस्कार मिला था। अब वर्ष 2025 के लिए प्रीति भारती का चयन हुआ है।

कड़े मानकों के बीच अकेला आवेदन

इस बार राज्य अध्यापक पुरस्कार की चयन प्रक्रिया पहले की अपेक्षा अधिक कड़ी रही। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024 में जिले से चार शिक्षकों ने आवेदन किया था, जिनमें से तीन शिक्षकों के नाम चयन के लिए भेजे गए थे। वहीं वर्ष 2025 में प्राथमिक विद्यालय नेवलगंज, हसनगंज की शिक्षिका प्रीति भारती ने ही आवेदन किया। अकेले आवेदन के बावजूद उन्होंने चयन प्रक्रिया के मानकों को पूरा किया और पुरस्कार के लिए चुनी गईं।

करंट लगने से युवक की मौत

घर में मोबाइल चार्जिंग पर लगाते समय हादसा, परिवार में कोहराम

तमसा संकेत, एजेंसी

उन्नाव। उन्नाव के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के सन्नी सराय में मंगलवार दोपहर एक 26 वर्षीय युवक की घर में करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान गंगासागर पुत्र गौरी के रूप में हुई है। इस घटना से परिवार में शोक का माहौल है। मृतक की पत्नी गर्भवती है और परिवार के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। परिजनों के अनुसार, गंगासागर मंगलवार दोपहर घर के अंदर किसी काम में लगा था। वह कमरे में अकेला था, तभी बिजली के तार में मोबाइल का चार्जर लगा रहा था उसी दौरान चपेट में आ गया। करंट लगने के बाद उसने अपनी मां को मदद के लिए आवाज दी। आवाज सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे तो वह बरामदे में अचेत पड़ा मिला। परिजनों ने तत्काल गंगासागर को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। मृतक की मां कमला ने बताया कि उनका बेटा घर के अंदर मोबाइल लगाने या बिजली से जुड़ा कोई काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक करंट उतर आया और वह उसकी चपेट में आ गया। उन्होंने बताया कि बेटे के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह अंदर पहुंचीं, लेकिन तब तक वह करंट लगने से नीचे गिर चुका था। कमला के मुताबिक, गंगासागर पहले एक कंपनी में काम करता था। बाद में उसने ऑटो खरीदा और उसे चलाकर परिवार का भरण-पोषण कर रहा था। ऑटो खरीदने के लिए उसने किस्त पर वाहन लिया था और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद करीब सालभर से उसकी किस्त जमा कर रहा था। परिजनों ने बताया कि गंगासागर की शादी लगभग छह साल पहले हुई थी। उसकी पत्नी गर्भवती है और वर्तमान में अस्पताल में भर्ती है। पति की आकस्मिक मौत की खबर से परिवार सदमे में है। कमला ने सरकार से परिवार की आर्थिक मदद की मांग की है। उनका कहना है कि परिवार की स्थिति ठीक नहीं है और बेटे की मौत के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी भी मुश्किल हो गई है। उन्होंने प्रशासन से नियमानुसार सहायता दिलाने की गुहार लगाई है। पुलिस का कहना है कि करंट लगने से युवक की मौत की सूचना मिली है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

सम्पादकीय

आर्थिकी के अच्छे दिन

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रहना इसलिए सुखद आश्चर्य का विषय है, क्योंकि ऐसे आंकड़े वैश्विक उथल-पुथल और विशेष रूप से ऊर्जा उत्पादों की ऊंची कीमतों के बाद भी सामने आए। अनेक अर्थशास्त्री ऐसी आशा नहीं कर रहे थे। इसलिए और भी, क्योंकि पिछले साल इसी तिमाही में अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.9 प्रतिशत रही थी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य चुनौती भरा दिखाई दे रहा था।

इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहने का एक बड़ा कारण घरेलू मांग कायम रहना है। इसके अलावा सरकारी कैपिटल खर्च, मैन्यूफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और एक्सपोर्ट ने भी जीडीपी वृद्धि में योगदान दिया। यह स्वाभाविक है कि जीडीपी के उम्मीद से अच्छे आंकड़ों पर प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की और इन्हें निराशावादियों के लिए झटका बताया। यह स्पष्ट है कि उनका संकेत उनकी ओर था, जो कुछ समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत बताए जाने के खीझ भरे दावे का समर्थन कर रहे थे। जीडीपी के आकर्षक आंकड़े यह भी रेखांकित कर रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिका से व्यापार समझौता न हो पाने के बाद भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रही है। चूंकि इसमें उन व्यापार समझौतों का योगदान रहा, जो पिछले कुछ समय में कई देशों के साथ हुए, इसलिए ऐसे समझौतों का सिलसिला कायम रहना चाहिए। इससे अर्थव्यवस्था को बल देने के साथ अमेरिका के दबाव का प्रतिकार करने में भी सफलता मिलेगी। 7.8 प्रतिशत विकास दर के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था एक बार फिर सबसे तेज बढ़ती आर्थिकी बनी, लेकिन भारत को इससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। विकास दर बढ़ने के साथ ही भारतीय नागरिकों की औसत आय बढ़ना भी आवश्यक है। इसके लिए भारत का लक्ष्य आठ प्रतिशत से अधिक विकास दर हासिल करना होना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए, क्योंकि एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था इस लक्ष्य को पाने की क्षमता रखती है और दूसरे ऐसी विकास दर ही देश को विकसित बनाने के लक्ष्य को आसान बना सकती है। इससे ही निर्धनता को दूर करने के उपायों को बल देने में सफलता मिलेगी। अब जब यह स्पष्ट है कि मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ ने जीडीपी को सहारा देने का काम किया, तब फिर इस सेक्टर की क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए। मैन्यूफैक्चरिंग के अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने भी जीडीपी को बल दिया। सबसे ज्यादा लोगों को काम देने वाला यह सेक्टर और फले-फूले, लेकिन गुणवत्ता के मानकों पर खरा उतरते हुए। यह देखने की जिम्मेदारी नीति-नियंताओं की है। उन्हें इसके प्रति भी सतर्क रहना होगा कि कमजोर मानसून अगली तिमाही की विकास दर को प्रभावित न करने पाए।

सफलता के मुख्य सूत्र

मानव जीवन में सफलता का मेरे चिन्तन से मुख्य सूत्र हैं की हम सदैव सही सोच से पारदर्शिता से अपने लक्ष्य की ओर हम सतत् प्रवाहमान रहे । सतत् प्रवाहमान रहने से समय कम ज्यादा कितना ही लगे परन्तु हमें सफलता अवश्य मिलती हैं । हर अच्छी सोच,कार्य,लक्ष्य का निर्धारण,विपत्ति का सामना, साहस -शौर्य,उम्र चाहे बचपन हो या पचपन ,सदैव एकाग्रता, सही दिशा, स्पष्ट लक्ष्य सूत्र है सफलता के । इन सबको इतनी गहराई से हम चाहे कि वह उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो । सफलता का यह ध्येय है की हमारा स्वभाव आदमी का खुद का भाव होता है ।स्वभाव में रहने वाले को ना किसी प्रकार का दुराव होता है और ना ही कोई तनाव होता है । इसलिए हम खुद के साथ जीने की सदैव आदत डालें और खुद के मंथन से ही कोई सुखद नवनीत निकालें । अनेकांत झलक रहा हैं। विभाव का अभाव हो, रहें स्वभाव में।अनेकांत सहज हो, वैचारिक मतभेद से क्यों रहें ताव में।मिल-जुल कर हम रहना सीखें , विनम्रता से हम कहना सीखें ,सुनना पड़े या करना पड़े कुछ भी इच्छा के विपरीत, तो सहना सीखें ।सरलता से किसी कटुता को नज़रअंदाज़ करना सीखें ,छोटी-मोटी बातों को दरकिनार करें , चुभ जाये यदि काँटा भी कभी तो हम सहजता से उसे निकाल फेंकें या शान्त रहे ।नम्रता और सरलता से जीवन को हम समृद्ध बनायें ।चित्त की उदारता का हम रसीला मिश्रण मिलायें ।सामंजस्य की मिठास से हम उसे सुस्वादु बनायें ।ये उत्तम और सफल सुखद जीवन के गुर हैं ,खुशहाल और शान्त जीवन के सुर हैं । जीवन को यह सरल-संतुष्ट सफल बनाता हैं ।

> प्रदीप छाजेड़

दुनिया जब बुरे दौर में है तब भारत के आर्थिक उजाले

> इस आर्थिक प्रदर्शन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि वृद्धि केवल एक क्षेत्र के सहारे नहीं टिकी है। विनिर्माण क्षेत्र में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि इस बात का संकेत है कि भारत धीरे-धीरे उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।

दुनिया आज जिस दौर से गुजर रही है, वह आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टियों से असाधारण चुनौतियों का दौर है। रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभाव, पश्चिम एशिया में तनाव, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा, वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने दुनिया की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सामने कठिन प्रश्न खड़े कर दिए हैं। ऐसे समय में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस मजबूती का परिचय दिया है, वह केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं, बल्कि बदलते भारत की सामर्थ्य का प्रमाण है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की 7.8 प्रतिशत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत को ऐसी उम्मीद के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसकी ओर दुनिया आश्चर्य और विश्वास दोनों के साथ देख रही है। इस विकास दर ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक शक्ति और आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी है एवं एक उजाला बिखेरा है। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वृद्धि ऐसे समय दर्ज हुई है, जब परिस्थितियां सामान्य नहीं थीं। महंगाई, ऊर्जा संकट, भू-राजनीतिक तनाव और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पथ मजबूत बना रहा। पिछले वर्ष इसी तिमाही में विकास दर 6.9 प्रतिशत थी। यानी एक वर्ष में आर्थिक वृद्धि की गति में उल्लेखनीय सुधार दिखाई दिया है। घरेलू मांग की मजबूती, सरकारी पूंजीगत व्यय, विनिर्माण, निर्माण और निर्यात जैसे क्षेत्रों का योगदान इस प्रदर्शन के पीछे महत्वपूर्ण रहा है। आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ तभी समझ में आता है, जब उसे उसके वैश्विक संदर्भ में देखा जाए। आज दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं केवल आर्थिक नीतियों से प्रभावित नहीं हो रहीं, बल्कि युद्ध, कूटनीतिक तनाव, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक संबंध भी उनकी दिशा तय कर रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक एवं रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। पश्चिम एशिया का तनाव ऊर्जा बाजार और वैश्विक आपूर्ति तंत्र के लिए चिंता पैदा करता है। इन परिस्थितियों में भारत का अपेक्षाकृत तेज आर्थिक विकास यह संकेत देता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने लिए ऐसे मजबूत घरेलू आधार तैयार किए हैं, जो बाहरी झटकों को सहने की क्षमता रखते हैं। यही वह परिवर्तन है जो भारत को केवल एक बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में आगे ले जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल घरेलू बाजार है। करोड़ों उपभोक्ताओं की मांग, बढ़ता मध्यम वर्ग, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार, बुनियादी ढांचे पर निवेश और बदलती उपभोग संस्कृति ने अर्थव्यवस्था को आंतरिक गति प्रदान की है। जब वैश्विक बाजार अनिश्चित हों, तब घरेलू मांग अर्थव्यवस्था के लिए सुरक्षा-कवच का काम करती है। इसीलिए वर्तमान विकास दर में घरेलू मांग की मजबूती को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। लंबे समय तक भारत की अर्थव्यवस्था को मुख्यतः सेवा क्षेत्र की शक्ति के रूप में देखा जाता रहा, लेकिन अब देश में उत्पादन बढ़ाने, घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने और बुनियादी ढांचे के विस्तार की दिशा में किए गए प्रयासों से औद्योगिक क्षेत्र के लिए नई संभावनाएं पैदा हुई हैं। निर्माण क्षेत्र भी रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सड़कें, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, आवास, औद्योगिक गलियारे और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश का प्रभाव केवल आर्थिक वृद्धि के आंकड़ों में नहीं दिखाई देता, बल्कि उससे भविष्य की आर्थिक क्षमता भी निर्मित होती है।

भारत की वर्तमान आर्थिक यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनाई गई नीतियों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले वर्षों में सरकार ने बुनियादी ढांचे, डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन, विनिर्माण, नए उद्यम, आत्मनिर्भरता, ऊर्जा सुरक्षा और औपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर लगातार जोर दिया है। जनधन खातों से लेकर डिजिटल भुगतान तक और राजमार्गों से लेकर रेलवे के आधुनिकीकरण तक, आर्थिक गतिविधियों का एक व्यापक तंत्र तैयार हुआ है। वस्तु एवं सेवा कर ने देश के बड़े बाजार को अधिक एकीकृत करने में भूमिका निभाई है। दिवाला एवं दिवालियापन संहिता जैसी व्यवस्थाओं ने कारोबारी वातावरण को अधिक व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं ने अनेक क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन और निवेश को बढ़ावा दिया है। इन नीतियों का वास्तविक मूल्यांकन केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि उनके परिणामों से होना चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद के ताजा आंकड़े इस दिशा में एक सकारात्मक संकेत अवश्य देते हैं। आम नागरिक के लिए आर्थिक विकास का अर्थ तभी सार्थक है, जब उसके जीवन में रोजगार के अवसर बढ़ें, आय में वृद्धि हो, महंगाई नियंत्रित रहे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों तथा जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार आए। सकल घरेलू उत्पाद हमें अर्थव्यवस्था की गति बताता है, लेकिन यह नहीं बताता कि उस विकास का लाभ समाज के विभिन्न वर्गों तक किस प्रकार पहुंच रहा है। इसलिए भारत की अगली चुनौती तेज विकास से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। आर्थिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी रोजगार है। विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र का विस्तार इसलिए आशाजनक है क्योंकि ये बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन भविष्य में भारत को ऐसे उद्योगों की आवश्यकता होगी, जो बड़ी संख्या में युवाओं को सम्मानजनक और स्थायी रोजगार दे सकें। भारत की युवा आबादी उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि उसे कौशल, शिक्षा, तकनीक और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलते हैं तो यही युवा शक्ति भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की सबसे बड़ी ऊर्जा बन सकती है।

भारत का लक्ष्य केवल आत्मनिर्भर बनना नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में नेतृत्वकारी भूमिका निभाना होना चाहिए। आत्मनिर्भरता का अर्थ दुनिया से अलग होना नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं को इतना मजबूत करना है कि भारत वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सके। आज दुनिया चीन के विकल्प के रूप में विभिन्न उत्पादन केंद्रों की तलाश कर रही है।

– ललित गर्ग

चार लाख से अधिक...

डॉ. शैलेश शुक्ला

मर रहा सूचना का अधिकार, निष्क्रिय हो देख रही है सरकार

सूचना का अधिकार आज खुद ही सांस के लिए संघर्ष कर रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। जो कानून आम आदमी को अफसर से सवाल पूछने की ताकत देता था, वह आज खुद अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहा है। आंकड़े डराने वाले हैं। देश में उनतीस सूचना आयोग हैं, एक केंद्रीय और अट्ठाईस राज्यों के। जून, 2025 तक इन सभी में कुल चार लाख तेरह हजार नौ सौ बहत्तर अपील और शिकायतें पेंडिंग थीं। केंद्रीय सूचना आयोग की ही बात करें तो एक फरवरी, 2026 में सरकार ने राज्यसभा में बताया कि वहां उनतीस हजार चौंतीस अपील और तीन हजार पांच सौ सतहत्तर शिकायतें यानी कुल बत्तीस हजार छह सौ ग्यारह मामले लंबित हैं। अगस्त, 2026 में यह संख्या चालीस हजार पार कर गई, जब छत्तीस हजार तीन सौ पचास अपील और तीन हजार सात सौ तैंतीस शिकायतें पोर्टल पर दिखीं। इसका सीधा अर्थ है कि जिस व्यक्ति ने गांव के हैंडपंप, राशन कार्ड या छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी मांगी, उसकी दूसरी अपील की सुनवाई दो साल बाद होगी। तब तक अधिकारी रिटायर हो चुका होगा और सवाल बेमानी हो जाएगा।

यह भीड़ मामलों की अधिकता से नहीं, कुर्सियां खाली रखने से बनी है। सरकार की सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारी नियुक्तियां न करना है। अक्टूबर,2025 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि केंद्रीय सूचना आयोग में चीफ का पद 14 सितंबर, 2025 से खाली है और दस में से आठ आयुक्तों के पद खाली हैं। दस में से आठ कुर्सियां खाली हों तो काम कैसे चलेगा। राज्यों में स्थिति और खराब है। जुलाई, 2024 से अक्टूबर, 2025 के बीच 29 में से छह आयोग अलग अलग अवधि में पूरी तरह बंद रहे क्योंकि वहां कोई आयुक्त ही नहीं था। हिमाचल प्रदेश और झारखंड अक्टूबर, 2025 तक बंद थे। जब आयोग ही बंद रहेगा तो नागरिक कहां जाएगा। दूसरी वजह है पुरानी कार्यपद्धति। एक आयुक्त साल में औसतन अट्ठाईस सौ मामलों का निपटारा करता है, जबकि हर साल 30,000 से ज्यादा नए मामले आ जाते हैं। एक गड्ढा भरते ही दो नए खुद जाते हैं। इस गति से पेंडेंसी कभी खत्म नहीं होगी। कई राज्यों में सुनवाई में दो साल लग रहे हैं।

तीसरी वजह सबसे गंभीर है और वह है सरकार की मंशा। आरटीआई कानून की धारा चार एक बी में लिखा है कि हर विभाग को 17 तरह की जानकारी खुद ही वेबसाइट पर डालनी होगी। बजट, वेतन, विदेश यात्रा, सरकारी गाड़ी, बंगला, ठेके, सब्सिडी के लाभार्थी, सब कुछ। इसे स्वतः प्रकटीकरण कहते हैं। सोच यह थी कि जानकारी पहले से सार्वजनिक होगी तो आरटीआई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर हकीकत में अस्सी फीसदी से ज्यादा विभाग इसका पालन नहीं करते। वेबसाइट पर दस साल पुराना डेटा पड़ा है या कुछ है ही नहीं। नतीजा एक ही सवाल पर हजारों आरटीआई आती हैं और आयोग दब जाता है। यह बोझ सरकार ने खुद बनाया है।

चार लाख से अधिक पेंडिंग मामले सिर्फ फाइल नहीं, चार लाख लोगों के टूटे भरोसे की कहानी हैं। इसी कानून से आदर्श सोसाइटी, कॉमनवेल्थ, टू जी जैसे घोटाले उजागर हुए। इसी से गरीब की पेंशन, छात्र की कॉपी, किसान का मुआवजा जैसे सवालों के जवाब मिले। जब सुनवाई दो साल बाद होगी तो अधिकारी को डर ही नहीं रहेगा। वह सोचेगा जानकारी रोक लूं, अपील होगी, दो साल टलेगा, तब तक मेरा तबादला हो जाएगा। यह डर खत्म होना भ्रष्टाचार की जीत है। सरकार अक्सर दुरुपयोग का आरोप लगाती है, पर सच्चाई यह है कि वह दुरुपयोग के बहाने उपयोग को ही खत्म कर रही है। नियुक्ति न करना, बजट न देना, स्टाफ न देना, यह कानून को बिना रद्द किए मारने की रणनीति लगती है।

इसे ठीक करने के लिए पांच ठोस कदम जरूरी हैं। पहला, नियुक्ति का तय कैलेंडर बने। जैसे यूपीएससी और चुनाव आयोग का कैलेंडर होता है, वैसे ही आयुक्तों का भी हो। कार्यकाल खत्म होने से तीन महीने पहले विज्ञापन निकले। पद तीस दिन से अधिक खाली रहे तो संबंधित सचिव की जवाबदेही तय हो। दूसरा, आयुक्तों की संख्या बढ़े और बेंच सिस्टम शुरू हो।

किसानों की ...

डॉ. मनोज चंद्रा

प्रदेश के किसानों की कृषि सुरक्षा का सशक्त आधार है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

मानसून का जुआ कहलाने वाली भारतीय कृषि को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सुरक्षा प्रदान कर प्रदेश सरकार एक क्रांतिकारी भूमिका निभा रही है। भारतीय कृषि की प्रकृति सदैव से मानसून और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील रही है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में असामयिक वर्षा, भीषण ओलावृष्टि और सूखे जैसी स्थितियाँ किसानों के लिए गहरा आर्थिक संकट पैदा कर देती हैं। एक किसान अपने सीमित संसाधनों और कठिन परिश्रम से फसल तैयार करता है, परंतु किसी एक प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। इसी जोखिम के प्रबंधन हेतु एक सशक्त तंत्र की आवश्यकता सदैव से महसूस की गई, ताकि कृषकों को ऋण के जाल से बचाकर उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा सके और खेती को एक लाभप्रद व्यवसाय के रूप में स्थापित किया जा सके।

किसानों की इसी संकट के स्थायी समाधान हेतु देश के मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पूरे देश में लागू किया। भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार यह योजना उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभावी ढंग से संचालित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, रोगों और कीटों से होने वाली फसल क्षति की स्थिति में बीमित किसानों को बीमा कवर के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अपनी विकास यात्रा के दौरान इस योजना ने पूर्ववर्ती फसल बीमा मॉडलों की विसंगतियों को दूर करते हुए एक अधिक पारदर्शी और किसान-हितैषी ढांचा तैयार किया है। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी किसान की आय का स्तर बना रहे और वह खेती को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित हो सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की संरचना और कार्यप्रणाली को किसानों की सुगमता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत खरीफ की 10 फसलों और रबी की 8 फसलों को अधिसूचित किया गया है। खरीफ फसलों के लिए किसान द्वारा देय प्रीमियम की दर को बीमित राशि का मात्र 2 प्रतिशत और रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत तक सीमित रखा गया है, जबकि वार्षिक नकदी फसलों हेतु यह दर अधिकतम 5 प्रतिशत निर्धारित है। शेष प्रीमियम की राशि का वहन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर अनुपात में किया जाता है। वित्त पोषण के लिए राज्य सरकार एस्क्रो अकाउंट और केंद्र सरकार एआईसी, नई दिल्ली के माध्यम से धन उपलब्ध कराती है। प्रदेश में लागू मॉडल 80-110 के अनुसार, कुल प्रीमियम के सापेक्ष 110 प्रतिशत तक की क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा देय होती है और उससे अधिक की राशि का भुगतान राज्य सरकार स्वयं करती है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में इस योजना की उपलब्धियाँ और जमीनी प्रभाव इसके बढ़ते आंकड़ों से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। उत्तर प्रदेश में इस योजना से जुड़ने वाले किसानों की संख्या में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जहाँ 30.40 लाख किसान योजना का हिस्सा बने थे, वहीं वर्ष 2024-25 में यह संख्या 31.18 लाख और वर्ष 2025-26 के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 39.25 लाख तक पहुँच गई है।

जरा हटके

समूह से जुड़ने के...

डॉ0 सीमा गुप्ता

उद्यमशीलता और स्वावलंबन से नई पहचान बना रहीं ग्रामीण महिलाएं

उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के संयुक्त एवं सुनियोजित प्रयासों से संचालित ग्रामीण आजीविका और महिला सशक्तीकरण की विविध योजनाओं ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर को पूरी तरह से बदलना शुरू कर दिया है। सरकार का यह स्पष्ट और दृढ़ मत है कि जब किसी समाज में एक महिला सशक्त होती है, तो उसके सकारात्मक प्रभाव से पूरा परिवार, आने वाली पीढ़ियां और अंततः पूरा राष्ट्र सशक्त होता है। इसी परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार करने के लिए राज्य भर में व्यापक स्तर पर एक मौन क्रांति का सूत्रपात किया गया है, जिसके अत्यंत उत्साहजनक परिणाम अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगे हैं। जनपद फिरोजाबाद के ग्रामीण अंचलों में यह ऐतिहासिक बदलाव आज स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। यहां की महिलाएं अब अपनी पारंपरिक झिझक और रूढ़िवादी सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर घर की चारदीवारी से बाहर निकल रही हैं तथा अपनी मेहनत एवं लगन से आर्थिक स्वतंत्रता की एक नई इबारत लिख रही हैं। विभिन्न सरकारी आजीविका मिशनों और महिला केंद्रित अभियानों के अंतर्गत जनपद फिरोजाबाद की ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के जो सार्थक प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं, वे आज पूरे प्रदेश के लिए एक उत्कृष्ट मॉडल के रूप में उभर रहे हैं।

इसी ऐतिहासिक और प्रेरणादायी बदलाव की एक जीवंत एवं सशक्त मिसाल जनपद फिरोजाबाद के ब्लॉक टूंडला स्थित ग्राम बसई की निवासी हेमलता रावत की जीवन यात्रा है। उच्च शिक्षित होने के बावजूद हेमलता के जीवन में वर्ष 2022 में एक ऐसा समय आया जब उन्हें अत्यंत कठोर पारिवारिक और मानसिक आघात का सामना करना पड़ा। उनके पति मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण अचानक लापता हो गए। इस आकस्मिक घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। घर के एकमात्र कमाने वाले सदस्य के चले जाने से परिवार के भरण-पोषण और विशेष रूप से अपनी दो मासूम बेटियों की परवरिश एवं उनकी शिक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी अचानक से हेमलता के अकेले कंधों पर आ गई।

इन बेहद कठिन, चुनौतीपूर्ण और विपरीत परिस्थितियों में भी हेमलता ने अपना धैर्य नहीं खोया। इसी दौरान, जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन में गांव-गांव चलाए जा रहे आजीविका संवर्धन और महिला जागरूकता कार्यक्रमों ने उनके जीवन में एक नई आशा की किरण का संचार किया। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी और प्रोत्साहन से प्रेरित होकर, 26 जनवरी 2020 को हेमलता अपने ग्राम की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर एक स्थानीय स्वयं सहायता समूह की सक्रिय सदस्य बन गईं।

समूह से जुड़ने के उपरांत हेमलता को न केवल एक मजबूत मानसिक और सामाजिक संबल प्राप्त हुआ, बल्कि सरकारी व्यवस्था के माध्यम से उन्हें आवश्यक प्रशासनिक सहयोग, मार्गदर्शन और उद्यमशीलता का प्रशिक्षण भी मिला। सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप समूह की बैठकों में नियमित प्रतिभागिता और बचत के अनुशासन का पालन करते हुए समूह के माध्यम से बीस हजार रुपये का ऋण प्राप्त किया और 20 अक्टूबर 2021 को अपने ही गांव में कॉस्मेटिक सामग्री की एक छोटी सी दुकान की नींव रखी।

अपने व्यवसाय को अधिक पेशेवर और लाभदायक बनाने की दृष्टि से, हेमलता ने सरकारी नोडल प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कौशल विकास का लाभ उठाया। उन्होंने सरकारी व्यवस्था के तहत निःशुल्क संचालित ब्यूटी पार्लर का आधिकारिक और तकनीकी प्रशिक्षण कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इस उन्नत प्रशिक्षण और नए कौशल को प्राप्त करने के पश्चात, उन्होंने अपनी छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान का सफलतापूर्वक विस्तार किया और उसे एक पूर्ण सुसज्जित ब्यूटी पार्लर के रूप में स्थापित कर दिया। उनके इस निर्णय ने न केवल उनके व्यवसाय को नई गति दी, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी स्थानीय स्तर पर एक बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करा दी।

आज हेमलता अपनी इस दुकान का सफल संचालन करने के साथ-साथ समूह सखी के रूप में अपने प्रशासनिक दायित्वों का भी अत्यंत कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रही हैं। अपनी इस बहुआयामी भूमिका के माध्यम से वह वर्तमान में प्रतिमाह पंद्रह से बीस हजार रुपये तक की एक बेहद सम्मानजनक और स्थिर आय अर्जित कर रही हैं। इस आर्थिक स्वतंत्रता ने उन्हें वह सामर्थ्य प्रदान किया है जिससे वह आज एक सिंगल मदर होने के बावजूद अपनी दोनों बेटियों को बिना किसी बाहरी मोहताज के, समाज के प्रतिष्ठित संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर पा रही हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव मजबूत कर रही हैं।

हेमलता रावत ने अपने गांव और आस-पास के क्षेत्रों की अन्य महिलाओं को भी जागरूक कर उन्हें स्वयं सहायता समूहों के इस महाभियान से जोड़ा, उनके निरंतर प्रयासों और कुशल नेतृत्व का ही यह परिणाम है कि उनके समूह से जुड़ी आठ अन्य महिलाओं को भी सरकारी पहल के अंतर्गत बैंक सखी और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी (बी.सी. सखी) जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सम्मानजनक रोजगार प्राप्त हुए हैं, जिससे उन महिलाओं के परिवारों का भी आर्थिक कायाकल्प हुआ है।

जनपद फिरोजाबाद में जिला प्रशासन के सतत प्रयासों से ऐसे हजारों प्रेरणादायक उदाहरण प्रतिदिन आकार ले रहे हैं। इस वृहद लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरे जनपद के सभी विकास खंडों में सघन कौशल विकास और आजीविका संवर्धन के व्यापक कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। विभिन्न सरकारी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण नोडल एजेंसियों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को उनकी व्यक्तिगत रुचि, शारीरिक क्षमता और स्थानीय संसाधनों की सुलभता के आधार पर पूरी तरह से निःशुल्क प्रशिक्षित किया जा रहा है।

इन बहुआयामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जनपद फिरोजाबाद की भौगोलिक और औद्योगिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए सिलाई-कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण, आचार-पापड़ व दलिया निर्माण, हस्तशिल्प, अगरबत्ती और मोमबत्ती निर्माण, जूट के पर्यावरण-अनुकूल बैग बनाने और आधुनिक जैविक खेती जैसे पारंपरिक और लाभकारी कार्यों को प्रमुखता से शामिल किया गया है।

इनमें मां-बेटे, चाची और ससुर, एक्सप्रेस-वे पर ट्रक में घुसी पिकअप, 14 घायल

खाटूश्याम से लौट रहे यूपी के 6 श्रद्धालुओं की मौत

घटना

तमसा संकेत, एजेंसी

मैनपुरी। यूपी के मैनपुरी के 21 श्रद्धालुओं से भरी पिकअप मंगलवार तड़के हरियाणा में सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से घुस गई। हादसे में मां, बेटे, चाची और ससुर समेत 6 लोगों की मौत हो गई। 14 लोग घायल हुए हैं। सभी राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के बाद पिकअप से वृंदावन जा रहे थे। हादसा पलवल में KMP एक्सप्रेस-वे पर हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए। लोग उछलकर सड़क पर जा गिरे।

- ड्राइवर सीट के बगल में बैठे व्यक्ति की गर्दन पिकअप में फंस गई थी।
- केएमपी में टक्कर के बाद क्षतिग्रस्त हुआ श्रद्धालुओं का पिकअप वाहन।
- हादसे में 14 लोग घायल हैं। पलवल के सिविल अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है।

ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति की गर्दन पिकअप की बॉडी में फंस गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि ड्राइवर को झपकी आने से हादसा हुआ। ड्राइवर ने पिकअप को लोहे के सरिए और जाल लगाकर डबल डेकर बनाया था। इससे उसकी ऊंचाई भी बढ़ गई थी। पुलिस ड्राइवर को नींद आना इस हादसे का कारण मान रही है। टाटा पिकअप से निकला था 21 श्रद्धालुओं का जत्था : पुलिस के मुताबिक, मैनपुरी जिले के किशनपुर मुरैया, मकोया, चांदा और आसपास के करीब 21 ग्रामीण रक्षाबंधन पर्व पर अपने गांवों से टाटा पिकअप से निकले थे। इन लोगों ने सोमवार की शाम को राजस्थान के खाटू श्याम और बालाजी के दर्शन किए थे। इसके बाद इनकी प्लानिंग मथुरा के वृंदावन में दर्शन करने की थी। सभी देर को ही पिकअप में सवार होकर मथुरा के लिए निकले थे।

पत्नी की मौत, पति, बेटा-बहू घायल

गांव मुर्गिया निवासी रामसेवक यादव अपनी पत्नी कमला देवी (60) व पुत्र रवि यादव और बहू रेखा यादव के साथ गए थे। हादसे में कमला देवी की मौत हो गयी। जबकि रामसेवक , रवि और रवि की पत्नी रेखा घायल हैं। इसी गांव के विनोद यादव अपनी पत्नी रेशमा देवी (45) के साथ गए थे। दुर्घटना में रेशमा देवी की भी मौत हो गयी है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पिकअप चालक सुधीर भी फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। फरार चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में रक्तदान शिविर, 200 यूनिट रक्त एकत्र

विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर लिया हिस्सा

तमसा संकेत, संवाददाता

साहिबाबाद। इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज (आईपीईसी) में रोटरी क्लब ऑफ गाजियाबाद नॉर्थ के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कॉलेज के छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस दौरान 200 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। आईपीईसी के वाइस चेयरमैन पुनीत अग्रवाल ने कहा कि रक्तदान महादान है। जरूरत के समय रक्त की उपलब्धता किसी व्यक्ति की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने रक्तदान करने वाले सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के योगदान की सराहना की। संस्थान के डीन एकेडमिक्स डॉ. अमित जैन ने विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को रक्तदान शिविर में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि

स्वैच्छिक रक्तदान मानव सेवा के साथ-साथ समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। रक्तदान शिविर के आयोजन में रोटेरियन शैलेश जैन, रोटेरियन संजीव जैन एवं रोटरी क्लब ऑफ गाजियाबाद नॉर्थ के सदस्यों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। कॉलेज प्रबंधन ने शिविर को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी रक्तदाताओं, चिकित्सा टीम, स्वयंसेवकों और रोटरी क्लब के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। शिविर के माध्यम से विद्यार्थियों और कॉलेज परिवार ने रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आने का संदेश दिया।

फास्ट न्यूज

कानपुर-विकास दुबे का नहीं बना मृत्यु प्रमाणपत्र

कानपुर। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर में मारे जाने के छह साल बाद भी उसका मृत्यु प्रमाणपत्र जारी नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम के दस्तावेजों और बॉडी डिस्पोजल स्लिप में पिता का नाम गलत दर्ज होने के कारण मामला अटका हुआ है। मंगलवार को हाईकोर्ट से आख्या मांगे जाने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिदत्त नेमि पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। उन्होंने पोस्टमार्टम प्रभारी के साथ करीब एक घंटे तक बंद कमरे में संबंधित अभिलेखों की जांच की।

बस्ती में युवक ने लगाया जमीन हड़पने का आरोप

बस्ती। बस्ती में जमीन के राजस्व अभिलेखों में हेरफेर का मामला सामने आया है। गोरखनाथ मंदिर में सेवा करने वाले दीना नाथ ने 3 लोगों पर आरोप लगाया है कि उनकी गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर उनके पिता शिव बरन को राजस्व रिकॉर्ड में मृत दिखा दिया गया। उनकी जमीन का हिस्सा दूसरे व्यक्ति के नाम दर्ज करा दिया गया। मामला दुबौलिया थाना क्षेत्र के देईडीहा बुजुर्ग गांव का है। दीना नाथ के मुताबिक, वह घर पर कम ही रहते हैं और गोरखनाथ मंदिर में सेवा करते हैं। आरोप है कि उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर आरोपियों ने उनके पिता को राजस्व अभिलेखों में मृत दर्शाया।

भाजपा के 50 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल

औरैया। औरैया में कांग्रेस ने भाजपा को झटका देते हुए 50 से ज्यादा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का दावा किया है। इन सभी ने मंगलवार को लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सदस्यता ली। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की मौजूदगी में यह सदस्यता ग्रहण की गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सरिता दोहरे के नेतृत्व और वरिष्ठ नेता श्रीधर मखलू पाण्डेय के मार्गदर्शन में औरैया के अलग-अलग इलाकों से आए भाजपा नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा।

कटोरा लेकर नगर निगम पहुंचे व्यापारी

सीएम ग्रिड की बदहाल सड़कों के खिलाफ किया प्रदर्शन

तमसा संकेत, एजेंसी

कानपुर। कानपुर में सीएम ग्रिड योजना के तहत चल रहे सड़क निर्माण कार्य और जलभराव की समस्या से परेशान व्यापारियों ने मंगलवार को नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में व्यापारी नगर निगम मुख्यालय पहुंचे और हाथों में कटोरा लेकर धरने पर बैठ गए। करीब आधे घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की और सड़कों की बदहाली, अधूरे निर्माण कार्य तथा जलनिकासी की समस्या को लेकर नाराजगी जताई। व्यापारी नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे, लेकिन नगर आयुक्त के मौके पर मौजूद नहीं होने के कारण व्यापारियों ने कर निर्धारण अधिकारी सीपी सिंह को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने जल्द से जल्द सड़क निर्माण और जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की।

दीपावली से पहले कारोबार प्रभावित होने की चिंता

व्यापारियों ने कहा कि दीपावली का त्योहार नजदीक है। ऐसे समय में बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ती है, लेकिन खराब सड़कों और जलभराव के कारण बाजारों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। ज्ञानेश मिश्रा ने दावा किया कि सीएम ग्रिड के चलते खराब हुई सड़कों और अव्यवस्थाओं का सीधा असर व्यापार पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दीपावली के सीजन में करीब 200 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर शहर की स्थिति खराब हो गई है। व्यापारियों की मांग है कि जिस तरह कानपुर को विकास की दिशा में ले जाने की बात कही जा रही है।

व्यापारियों का कहना है कि सीएम ग्रिड के काम के कारण लंबे समय से सड़कें खुदी पड़ी हैं। जगह-जगह गड्ढे और निर्माण सामग्री होने के कारण दुकानों तक माल पहुंचाने में भी दिक्कत होती है। दो पहिया वाहन, ई-रिक्शा और अन्य वाहन कई बार गड्ढों में फंस जाते हैं। बारिश के दौरान स्थिति और खराब हो जाती है, क्योंकि पानी भरने के बाद सड़क और गड्ढों का अंतर स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इससे वाहन चालकों और राहगीरों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है।

मार्बल मार्केट से नवीन मार्केट तक सड़कों की हालत खराब

व्यापारियों ने कहा कि मार्बल मार्केट, यशोदा नगर और नवीन मार्केट समेत कई प्रमुख कारोबारी इलाकों में सड़कें बुरी तरह टूटी हुई हैं। इसके अलावा परेड, मूलगंज चौराहा और साकेत नगर में भी सड़क निर्माण के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि कई जगह सड़कें इतनी खराब हैं कि उन पर चलना भी मुश्किल हो गया है। जगह-जगह गड्ढे होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी होती है और दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है।

रामपुर में तीन किलो अफीम के साथ छह आरोपी गिरफ्तार

पुलिस-एसओजी टीम ने तमंचा-कारतूस, बरामद किए

तमसा संकेत, एजेंसी

रामपुर। भोट थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के कब्जे से करीब तीन किलो अफीम बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये है। पुलिस ने बताया कि संयुक्त टीम ने मंगलवार दोपहर लाला वाला बाग से आगे नई कॉलोनी की तरफ जाने वाले तिराहे पर कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों में बिलासपुर निवासी गगनदीप सिंह और सर्वजीत सिंह, भोट क्षेत्र के खूटांखेड़ा निवासी किशनदीप सिंह, उत्तराखंड के रुद्रपुर निवासी प्रभजोत सिंह और दीपक शर्मा तथा बिलासपुर क्षेत्र के नगलिया खुर्द निवासी वैभव कुमार शामिल हैं। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने मंगलवार शाम 6:00 बजे बताया कि आरोपियों के

कब्जे से तीन किलो अफीम के अलावा 315 बोर का एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस, छह मोबाइल फोन और 9,670 रुपये नकद बरामद किए गए। इसके साथ ही एक स्कॉर्पियो गाड़ी को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत सीज किया गया है। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना भोट में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 8/18/25/29/60 और आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

धीरेंद्र प्रताप सिंह अपहरण-हत्या मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में धीरेंद्र प्रताप सिंह के अपहरण के बाद हुई हत्या की घटना में शामिल एक वांछित अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, घटना के खुलासे और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए गठित टीमों ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्यों तथा स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से कार्रवाई की। इसी क्रम में पुलिस ने 1 सितंबर 2026 को ओमकार साहू पुत्र माधवराम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की उम्र करीब 24 वर्ष है। वह वर्तमान में खरगापुर, थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ में रह रहा था। उसका मूल निवास ग्राम सिमरिया, जनपद बेमेतरा, छत्तीसगढ़ बताया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतक की फॉर्च्यूनर कार की एक चाबी, 1,466 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं।

परिवहन आयुक्त ने बस्ती में ड्राइविंग लाइसेंस में गड़बड़ी पर दो मोटरयान निरीक्षक को किया निलंबित

परिवहन आयुक्त ने बस्ती में ड्राइविंग लाइसेंस में गड़बड़ी पर दो मोटरयान निरीक्षक को किया निलंबित

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। बस्ती के उप संभागीय परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता सामने आने के बाद परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में निर्धारित प्रक्रिया और जरूरी सत्यापन के बिना बड़ी संख्या में ड्राइविंग लाइसेंस मंजूर किए जाने का मामला सामने आया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवहन आयुक्त ने मोटरयान निरीक्षक संजय कुमार दास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं मोटरयान निरीक्षक सीमा गौतम के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों अधिकारियों के खिलाफ सतर्कता जांच के लिए भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भी पत्र भेजा गया है।

998 ड्राइविंग लाइसेंस में नहीं हुई जरूरी जांच

जांच के दौरान सामने आया कि बस्ती कार्यालय में कुल 998 ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे पाए गए, जिनमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक जांच-पड़ताल नहीं की गई थी। इनमें मोटरयान निरीक्षक संजय कुमार दास द्वारा 785 ड्राइविंग लाइसेंस और मोटरयान निरीक्षक सीमा गौतम द्वारा 213 ड्राइविंग लाइसेंस बिना जरूरी जांच-पड़ताल के मंजूर किए जाने का मामला सामने आया।

नियमविरुद्ध जारी लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू

परिवहन आयुक्त ने बताया कि जांच में नियमविरुद्ध पाए गए ड्राइविंग लाइसेंसों को रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग संबंधित लाइसेंसों और उनके रिकॉर्ड का परीक्षण कर रहा है। जांच में जिन लाइसेंसों को निर्धारित नियमों के विपरीत जारी किया जाना पाया गया है, उनके संबंध में नियमानुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलने के लिए किए गए कई आवेदनों में भी अनियमितता सामने आई है। जांच में पाया गया कि आवेदकों की ओर से लगाए गए पते के प्रमाणों का आवश्यक सत्यापन नहीं कराया गया। इस तरह बिना पर्याप्त सत्यापन के लाइसेंस में पता बदलने की प्रक्रिया पूरी किए जाने को भी विभाग ने गंभीरता से लिया है। अब ऐसे मामलों में भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। विभाग का उद्देश्य यह पता लगाना है कि लाइसेंस जारी करने में हुई अनियमितता केवल लापरवाही का परिणाम थी या इसके पीछे किसी अन्य स्तर पर भी मिलीभगत अथवा अनियमितता की भूमिका थी।

पुराने लाइसेंस की कॉपी भी कई आवेदनों में नहीं मिली

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि कई मामलों में आवेदन के साथ पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी तक अपलोड नहीं की गई थी। इसके बावजूद संबंधित आवेदनों को आगे बढ़ाकर लाइसेंस जारी किए गए। विभागीय जांच में इसे निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी माना गया है। अधिकारियों की ओर से आवेदन में उपलब्ध दस्तावेजों और ऑनलाइन रिकॉर्ड का जरूरी सत्यापन किया जाना था, लेकिन कई मामलों में यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई।

सेवा प्रदाता कंपनी के कर्मचारियों पर भी कार्रवाई

जांच में सेवा प्रदाता कंपनी के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी सामने आई है। विभाग की ओर से ऐसे कर्मचारियों को सेवा से हटाने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। इसके अलावा संबंधित फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। विभाग ने फर्म की ओर से जमा की गई सिक्योरिटी यानी बैंक गारंटी जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। दोनों मोटरयान निरीक्षकों के खिलाफ सतर्कता जांच के लिए भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पत्र भेजा गया है। इससे मामले में विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ सतर्कता स्तर पर भी जांच की जाएगी।

भूमिका : 10 नवीन परियोजनाओं को सशर्त स्वीकृति की संस्तुति, किसानों और युवाओं को मिलेगा लाभ

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दे रही प्रदेश सरकार

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रदेश सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करने तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के निर्माण में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उप मुख्यमंत्री ने

> खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नीति-2023 के अंतर्गत प्राप्त निवेश प्रस्तावों के समयबद्ध परीक्षण एवं आवश्यक अनुमोदन की प्रक्रिया निरंतर जारी है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर कृषि उपज का बेहतर मूल्य संवर्धन हो, किसानों की आय में वृद्धि हो तथा युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जा सकें।

खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं, अनुदानों एवं प्रोत्साहनों की व्यापक जानकारी उद्यमियों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी जनजागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक उद्यमियों को इस क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि किसानों की उपज को बेहतर बाजार एवं उचित मूल्य मिल सके तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ें। इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग श्री बी.एल. मीणा की अध्यक्षता में खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय में उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अंतर्गत गठित एप्रेजल समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पोर्टल पर प्राप्त नवीन निवेश प्रस्तावों का परीक्षण किया गया तथा समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में प्राप्त कुल 12 नवीन आवेदनों पर विचार किया गया। परीक्षण के उपरांत इनमें से 10 प्रस्तावों को आवश्यक शर्तों की पूर्ति के अधीन स्वीकृति हेतु संस्तुति प्रदान की गई। संस्तुत परियोजनाओं में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। इनमें कैटल फीड, अनाज एवं रिफाइंड मसाले, मूंगफली प्रसंस्करण, फ्रोजन एवं अन्य खाद्य उत्पाद, रेडी-टू-कुक उत्पाद, तेल-आटा-दाल-बेसन निर्माण, दाल मिल तथा फ्रोजन फ्रूट्स एवं वेजिटेबल प्रोसेसिंग जैसी इकाइयां शामिल हैं। कई प्रस्तावों में इकाइयों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। बैठक में एक प्रस्ताव को अभिलेखों के आधार पर पात्रता पूरी न होने के कारण निरस्त किया गया। वहीं, एक अन्य प्रस्ताव में प्लांट एवं मशीनरी से संबंधित आवश्यक विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद आगामी एप्रेजल समिति की बैठक में विचार किए जाने का निर्णय लिया गया।

जनगणना- 2027 की तैयारियों की समीक्षा, जिलाधिकारी विशाख जी ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। जिलाधिकारी श्री विशाख जी0 की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनगणना-2027 के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनगणना की तैयारियों, कार्मिकों की उपलब्धता, प्रशिक्षण, चार्ज निर्धारण, मानचित्रों के सत्यापन तथा एचएलबी/ईवी के पुनर्गठन की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि आगामी जनगणना हेतु सितंबर में सभी आवश्यक कार्मिकों की उपलब्धता एवं तैनाती सुनिश्चित कर ली जाए।

गणनाकर्मियों, पर्यवेक्षकों एवं फील्ड ट्रेनरों की सूची समय से तैयार कर प्रशिक्षण की सभी व्यवस्थाएं पहले से पूर्ण करने को कहा गया। उन्होंने अधिक जनसंख्या वाले एचएलबी को भौगोलिक निरंतरता को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार विभाजित कर उप-गणना ब्लॉक

बनाने तथा गणनाकर्मियों पर कार्यभार संतुलित रखने के निर्देश दिए। चार्ज एवं पर्यवेक्षण क्षेत्र के निर्धारण में मानचित्रों का मिलान तथा स्थलीय सत्यापन अनिवार्य रूप से कराने को कहा गया। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि एक ही कर्मचारी की विभिन्न चार्जों में दोहराई गई ड्यूटी न लगे तथा यथासंभव कर्मचारी के निवास स्थान अथवा कार्यस्थल के अनुरूप तैनाती की जाए। पिछली बार जिन विभागों से कार्मिक उपलब्ध कराने अथवा कार्यमुक्ति के संबंध में समस्याएं आई थीं, उन्हें चिन्हित कर समय से पत्राचार एवं कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कार्यमुक्ति/छूट के प्रकरणों की कड़ाई से समीक्षा करने तथा बिना उचित कारण के कार्मिकों को जनगणना कार्य से मुक्त न करने के निर्देश दिए। उपलब्ध कार्मिक आंकड़ों तथा वर्ष 2024 के सामान्य निर्वाचन से संबंधित आंकड़ों का मिलान कर आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में चार्ज रजिस्टर की प्रगति, अभिलेखों के प्रेषण एवं प्राप्ति तथा लंबित भुगतान प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी कार्यों को समयबद्ध एवं त्रुटिरहित ढंग से पूर्ण करने तथा एक समान अभिलेख के आधार पर सूचनाएं अद्यतन रखने के निर्देश दिए। इस बैठक में डॉ गौरव पाण्डेय , जनगणना उप निदेशक, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) श्री राकेश कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त श्री अभिनव रंजन सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

3 महीने से बंद है दिल्ली गेट-हरीपर्वत रोड, अब पाइप लाइन डाली जाएगी

हरीपर्वत पर फिर सड़क की खुदाई शुरू

परेशानी

तमसा संकेत, एजेंसी

आगरा। आगरा में हरीपर्वत चौराहे पर सीएम ग्रिड योजना के तहत चल रहे काम ने लोगों की परेशानी एक बार फिर बढ़ा दी है। पिछले तीन महीने से निर्माण कार्य के चलते दिल्ली गेट से हरीपर्वत जाने वाली सड़क बंद है। कुछ दिनों से सड़क को दुरुस्त करने और डिवाइडर बनाने का काम चल रहा था।

इससे लोगों को जल्द सड़क खुलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब एक बार फिर सड़क की खुदाई शुरू हो गई हर्त चौराहा-मदिया कटरा मार्ग पर रवि हॉस्पिटल तक सीएम ग्रिड योजना के तहत काम चल रहा

है। मंगलवार को एक साथ तीन जेसीबी से सड़क खोदी गई। बताया जा रहा है कि अब यहां पाइप लाइन डाली जाएगी। ऐसे में सड़क पर यातायात शुरू होने में अभी और समय लग सकता है। सीएम ग्रिड योजना के तहत यह काम जून में शुरू हुआ था। तब से दिल्ली गेट से हरीपर्वत की ओर जाने वाली सड़क पूरी तरह बंद है। निर्माण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से गुजरना पड़ रहा है और आसपास के इलाकों में यातायात का दबाव बढ़ गया है। कुछ दिन पहले पाइप लाइन डालने का काम पूरा होने के बाद सड़क से बैरिकेडिंग हटाई जाने लगी थी। डिवाइडर भी बनाए जा रहे थे। इससे लोगों को लगा था कि जल्द ही सड़क यातायात के लिए खोल दी जाएगी और रोजाना लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। सड़क को खोलने की उम्मीद कर रहे लोगों को उस समय झटका लगा, जब इसी सड़क पर दोबारा खुदाई शुरू कर दी गई।

मंगलवार को तीन जेसीबी मशीनें सड़क खोदती नजर आईं। बताया गया है कि पहले नगर निगम की ओरसे सीवर लाइन डाली गई थी। अब पाइप लाइन डालने के लिए उसी सड़क की दोबारा खुदाई की जा रही है। पाइप लाइन डालने का काम अभी शुरू हुआ है। ऐसे में इसे पूरा करने में समय लग सकता है। सड़क की खुदाई के चलते फिलहाल यातायात एक लेन से ही संचालित होने की संभावना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पिछले तीन महीने से बंद है। बार-बार खुदाई होने से निर्माण कार्य कब पूरा होगा और पूरी सड़क पर यातायात कब शुरू होगा, इसे लेकर असमंजस बना हुआ है। लोगों को अभी जाम और परेशानी से जल्द राहत मिलती नहीं दिख रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क करीब तीन महीने से बंद है। लंबे समय से निर्माण कार्य के कारण पहले ही लोगों को परेशानी हो रही है। अब सड़क की दोबारा खुदाई शुरू होने से यह साफ नहीं है कि निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा और पूरे मार्ग पर यातायात कब बहाल किया जाएगा।लोगों का कहना है कि बार-बार सड़क खोदे जाने के कारण जाम और आवागमन की समस्या बनी हुई है। फिलहाल उन्हें जल्द राहत मिलती नजर नहीं आ रही है।

बताया जा रहा है कि इससे पहले नगर निगम की ओर से इसी सड़क पर सीवर लाइन डालने का काम किया गया था। अब पाइपलाइन डालने के लिए सड़क की दोबारा खुदाई की जा रही है। पाइपलाइन का काम अभी शुरू हुआ है, इसलिए इसके पूरा होने में भी समय लगने की संभावना है। सड़क की खुदाई के कारण फिलहाल यातायात एक लेन से संचालित किए जाने की स्थिति बन सकती है।

मेरठ में किसानों की महापंचायत बनी अनिश्चितकालीन धरना

1000 किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ कमिश्नरी पहुंचे

तमसा संकेत, एजेंसी

मेरठ। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू टिकैत) की महापंचायत चल रही है। इसमें तीनों तहसीलों से करीब 1000 किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ कमिश्नरी परिसर पहुंचे हैं। कमिश्नरी के चारों तरफ 100 से अधिक ट्रैक्टर-ट्रॉलियां खड़ी हैं। किसान अपनी लंबित मांगों को लेकर कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन और घेराव कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा- जिस बच्चे के परिवार RSS ट्रेनिंगशुदा होंगे उन्हीं के बच्चों को नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा- हमनें शिक्षकों का शिक्षक प्रकोष्ठ बना रखा है। लेकिन कुछ BSA कहते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है। आरएस-एस का रजिस्ट्रेशन है क्या भई। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, आप यहीं रुकिए। इतना कहते ही किसानों ने पंचायत को अनिश्चि-तकालीन धरने में बदलने की घोषणा कर दी है। किसानों के लिए संगठन

की ओर से भंडारे की व्यवस्था की गई है, जहां हजारों किसानों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है। महापंचायत को लेकर भाकियू जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने सोमवार को जिले के कई गांवों और तहसील क्षेत्रों में बैठक कर किसानों से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की थी। महापं-चायत में पहुंच रहे किसान मोडिफाइड ट्रैक्टर लेकर पहुंच रहे हैं। पंचायत स्थल पर किसानों के लिए खाने की भी व्यवस्था की गई है और फिलहाल किसान खाना खा रहे हैं। इसके बाद भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।

फास्ट न्यूज

मुरादाबाद में एक्सीडेंट में युवक की मौत

बिलारी। बिलारी थाना क्षेत्र के रुस्तमनगर सहसपुर में सोमवार रात तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल घर लौट रहे युवक को टक्कर मार दी। हादसे में 24 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। हरिओम सोमवार रात करीब 8:30 बजे काम खत्म कर पैदल घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि हरिओम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

नगर निगम में 7 भ्रष्ट अफसर-कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी

कानपुर। कानपुर नगर निगम में टेंडर धांधली और माफियावाद के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ने के साथ कई और भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों पर गाज गिरना तय है। अब सात और अफसरों-कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी है। इनमें तीन कर्मचारी और चार अभियंता शामिल हैं। नगर निगम की ओर से इनके निलंबन की संस्तुति शासन को भेजी जा रही है। नगर निगम में भ्रष्टाचार की जांच कई स्तरों पर चल रही है। एसआईटी, सीडीओ की अगुवाई वाली कमेटी और खुफिया जांच भी की जांच कर रही हैं।

बदायूं में किसान का शव चकरोड पर मिला

बदायूं। बदायूं में खेत पर धान की फसल की रखवाली करने गए एक किसान का शव सुबह चकरोड पर मिला। किसान के गले में बान उलझा हुआ था। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। किसान की मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। यह घटना उझानी कोतवाली क्षेत्र के ननाखेड़ा गांव की है।

पिकअप से टकराई क्रेटा, तीन घायल

ड्राइवर को नींद की झपकी आने से हुआ हादसा

तमसा संकेत, एजेंसी

मथुरा। मथुरा के नौहझील क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह करीब 8 बजे क्रेटा कार आगे चल रही पिकअप से टकरा गई। हादसे में क्रेटा सवार तीन लोगों को मामूली चोटें आईं। पुलिस ने घायलों को सीएचसी भेजा। हादसा माइलस्टोन 61.100 के पास हुआ। आजमगढ़ निवासी आकाश पटेल पिकअप लेकर नोएडा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही क्रेटा के चालक गौरव निवासी कंकरखेड़ा, मेरठ को नींद की झपकी आ गई। इससे कार बेकाबू होकर पिकअप से टकरा गई। हादसे में गौरव, कुसुम और आरती को चोटें आईं। वहीं गौरव की पत्नी प्रमिला

सुरक्षित हैं। टक्कर से दोनों वाहनों को नुकसान हुआ। सूचना मिलने पर पीआरवी 5837 और बाजना कट मोबाइल पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दुर्घट-नाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो गया। पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में हादसे की वजह चालक को नींद की झपकी आना सामने आई है। फिलहाल मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।

बीसीआई की मंजूरी अटकी, सरकारी संस्थानों के छात्र परेशान, निजी कॉलेजों को मिल चुकी अनुमति

700+ लॉ सीटों पर प्रवेश रुका

तमसा संकेत, एजेंसी

आगरा। सत्र 2026-27 में विधि की पढ़ाई करने की तैयारी कर रहे आगरा के छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। आगरा कॉलेज और डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में एलएलबी और बीए-एलएलबी की 700 से अधिक सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया अटक गई है। दोनों संस्थानों को अब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से मंजूरी नहीं मिली है। वहीं, आगरा मंडल के 20 निजी लॉ कॉलेजों को बीसीआई की अनुमति मिल चुकी है। सरकारी संस्थानों में कम फीस में पढ़ाई का विकल्प उपलब्ध होने के बावजूद मंजूरी में देरी से छात्रों के सामने निजी कॉलेजों में प्रवेश लेने की मजबूरी बन रही है। विधि संकाय प्रभारी डीसी मिश्रा ने बताया कि बीसीआई की मंजूरी के लिए जुलाई में आवेदन किया गया था।

अभी तक अनुमोदन नहीं मिला है। बिना बीसीआई की अनुमति के नए सत्र में प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। आगरा मंडल में आगरा के 7, मथुरा के 8, मैनपुरी के 3 और फिरोजाबाद के 2 निजी लॉ कॉलेजों को बीसीआई से मंजूरी मिल चुकी है। इन कॉलेजों में एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने में करीब 2 लाख रुपए तक खर्च आता है।

वहीं, बीए-एलएलबी की फीस और अन्य खर्च मिलाकर 3 से 4 लाख रुपए तक पहुंच सकते हैं। सरकारी संस्थानों में कम फीस और बेहतर विकल्प होने के कारण बड़ी संख्या में छात्र आगरा कॉलेज और विश्वविद्यालय में प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बीसीआई की मंजूरी में देरी के चलते छात्रों के सामने निजी कॉलेजों में प्रवेश लेने का दबाव बढ़ रहा है। छात्रों का कहना है कि सरकारी संस्थानों में प्रवेश नहीं खुला तो आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों के लिए महंगे निजी कॉलेजों में कानून की पढ़ाई करना मुश्किल होगा।

आगरा कॉलेज में 600 सीटें, फीस भी काफी कम

आगरा कॉलेज का विधि संकाय यूनिवर्सिटी कैंपस से अलग संचालित होता है। यहां एलएलबी की 300 और बीए-एलएलबी की 300 सीटें हैं। यानी कुल 600 सीटों पर नए सत्र में प्रवेश होना है। आगरा कॉलेज में पढ़ाई की फीस निजी संस्थानों की तुलना में काफी कम है। एलएलबी की सालाना फीस करीब 4,300 रुपए है। तीन साल की पूरी पढ़ाई करीब 12 से 13 हजार रुपए में पूरी हो जाती है। वहीं, बीए-एलएलबी की फीस करीब 16,500 रुपए सालाना है।

आगरा कॉलेज विधि में प्रवेश की जानकारी लेते छात्र।

यूनिवर्सिटी कैंपस में तैयार नई बिल्डिंग, 120 सीटों पर प्रवेश की तैयारी

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय कैंपस में लॉ कॉलेज की नई बिल्डिंग भी बनकर तैयार है। विश्वविद्यालय इसी सत्र से एलएलबी और बीए-एलएलबी में 120 सीटों पर प्रवेश शुरू करना चाहता है। प्रभारी डॉ. राजीव वर्मा ने बताया कि कॉलेज की ओर से तैयारियां पूरी हैं, लेकिन प्रवेश शुरू करने के लिए बीसीआई की अनुमति का इंतजार किया जा रहा है।

200 मोबाइल पुलिस ने लौटाए

एसएसपी ने 34 लाख कीमत के फोन उनके मालिकों को सौंपे

तमसा संकेत, एजेंसी

अलीगढ़। अलीगढ़ पुलिस ने चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की सर्विलांस टीम ने 200 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए। मंगलवार को एसएसपी नीरज कुमार जादौन की मौजूदगी में बरामद मोबाइल उनके स्वामियों को वापस किए गए। बरामद मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 34 लाख रुपये बताई गई है। मोबाइल वापस मिलने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई के लिए आभार जताया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मोबाइल फोन की बरामदगी का अभियान लगातार जारी रहेगा और समय-समय पर बरामद किए गए मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों

को सौंपे जाएंगे। एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि अलीगढ़ पुलिस की सर्विलांस टीम मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए लगातार काम कर रही है। टीम ने पिछले एक वर्ष के दौरान कुल 1,441 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार बरामद किए गए सभी मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाए जा चुके हैं। इन मोबाइल फोन की कुल अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 64 लाख रुपये है। पुलिस की तकनीकी टीम लगातार ऐसे मोबाइल फोन को ट्रेस करने में जुटी है, जिनके चोरी या गुम होने की शिकायत पुलिस के पास दर्ज कराई गई है।

तकनीकी मदद से ट्रेस किए जा रहे चोरी हुए मोबाइल

पुलिस की सर्विलांस टीम मोबाइल फोन की लोकेशन और तकनीकी जानकारी के आधार पर उन्हें ट्रेस करने का काम कर रही है। शिकायत मिलने के बाद मोबाइल फोन से संबंधित उपलब्ध तकनीकी जानकारी का विश्लेषण किया जाता है।

इसके आधार पर पुलिस टीम मोबाइल की तलाश कर उसे बरामद करने का प्रयास करती है।

अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक तकनीक और सर्विलांस सिस्टम की मदद से पुलिस को चोरी एवं गुम हुए मोबाइल फोन बरामद करने में लगातार सफलता मिल रही है।

एसएसपी ने लोगों से की तत्काल सूचना देने की अपील

एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने लोगों से अपील की कि मोबाइल फोन या सिम कार्ड गुम होने अथवा चोरी होने की स्थिति में देरी न करें। घटना की जानकारी तत्काल संबंधित थाने की पुलिस को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन चोरी होने के बाद केवल पुलिस को सूचना देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों को अपने स्तर से भी जरूरी सुरक्षा कदम उठाने चाहिए।

योगी सरकार में संवर रही कान्हा की नगरी, 30 हजार करोड़ के मास्टर प्लान से वैश्विक धार्मिक केंद्र बन रहा मथुरा-वृंदावन

तमसा संकेत, संवाददाता

मथुरा। योगी सरकार के नौ वर्ष के कार्यकाल में मथुरा-वृंदावन और पूरे ब्रज क्षेत्र में विकास की तस्वीर तेजी से बदल रही है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के गठन के बाद से ब्रज को अयोध्या और काशी की तर्ज पर वैश्विक धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़े स्तर पर काम हुआ है। करीब 30 हजार करोड़ रुपये के मास्टर प्लान के तहत सड़क, यातायात, घाट, मंदिर कॉरिडोर, पार्किंग और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, जबकि कई पर काम जारी है। बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए 15.4 किलोमीटर लंबे वृंदावन बाईपास को 1,645 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है। यह एनएच-19 और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। मथुरा-वृंदावन के बीच लगभग 470 करोड़ रुपये की लागत से फोरलेन और एलिवेटेड रोड का निर्माण भी जारी है। सीएम ग्रिड योजना के तहत

श्रीकृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र समेत शहर के प्रमुख मार्गों के विकास, सीसी रोड, भूमिगत केबलिंग और फुटपाथ निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं। ब्रज की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए विश्राम घाट से केशी घाट तक तटीय विकास और सौंदर्यीकरण कराया गया है। वृंदावन में अक्रूर घाट का निर्माण तथा यमुना पर केबल स्टे सस्पेंशन ब्रिज की योजना पर काम हो रहा है। ब्रज क्षेत्र के 100 से अधिक प्राचीन कुंडों और सरोवरों का ईको-रेस्टोरे-शन कर उन्हें पुनर्जीवित किया गया है। प्रमुख धार्मिक स्थलों पर फसाड और हेरिटेज लाइटिंग से रात में भी ब्रज की भव्यता निखर रही है। श्रद्धालुओं को जाम और पार्किंग की समस्या से राहत देने के लिए वृंदावन में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के पास करीब 38 करोड़ रुपये की लागत से मल्टीलेवल पार्किंग बनाई गई है। गोवर्धन और बरसाना में भी बड़े पार्किंग स्थल विकसित किए गए हैं। वृंदावन और बरसाना में आधुनिक टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर तैयार किए गए हैं। मथुरा-वृंदावन के बीच ई-बस सेवा और चार्जिंग स्टेशन की सुविधा भी शुरू की गई है। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने और दर्शन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में कॉरिडोर की योजना पर काम चल रहा है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र के मार्गों और चौराहों को हेरिटेज लाइटिंग व फसाड डेवलपमेंट से संवारा गया है। गोवर्धन के 21 किलोमीटर लंबे परिक्रमा मार्ग और बरसाना परिक्रमा मार्ग पर शेड, होल्डिंग एरिया, पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। मथुरा-वृंदावन को सुरक्षित बनाने के लिए सेफ सिटी परियोजना के तहत 5000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

पृष्ठ 01 का शेष...

सुप्रीम कोर्ट ने जंतर...

यानी पुलिस की ओर से इन मामलों में आगे की कार्रवाई जारी रखने के बजाय उन्हें समाप्त करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आंदोलन से संबंधित 13 FIR पर आगे की कार्रवाई समाप्त करने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, प्रदर्शन के दौरान मारपीट, तोड़फोड़ या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोपों से जुड़े मामलों को अलग रखा गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यह फैसला इसी मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर लिया गया है। इसे भविष्य के अन्य मामलों में स्वतः लागू होने वाली कानूनी मिसाल नहीं माना जाएगा।

मोदी की फिर अपील...

देश को यही रफ्तार बनाए रखनी होगी और आगे भी तेजी से विकास करना होगा। उन्होंने कहा, विदेश में घूमने के लिए यात्राएं करने और विदेश में शादी करने से बचना चाहिए। लोगों को मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पीएम ने यह भी कहा, जितना ज्यादा स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाएगा, भारत उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब देश की युवा पीढ़ी को एक विकसित भारत सौंपा जाएगा। दरअसल, राहुल लगातार 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम कर रहे हैं। राहुल ने अब तक कोटा, देहरादून, प्रयागराज और पुणे में 4 कार्यक्रम किए हैं। इसमें उन्होंने पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी, महंगी शिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को उठाए। नॉलेज में जानें- PM मोदी की पिछली अपील के बाद भारत ने कितना सोना खरीदा, सोना खरीदने से रुपया कैसे कमजोर होगा, इसका महंगाई पर असर और फिजिकल गोल्ड की जगह कहां निवेश किया जा सकता है? भारत अपने इस्तेमाल का करीब 99% सोना विदेशों से खरीदता है। 2025-26 में सोने का ये इम्पोर्ट बिल करीब 6.4 लाख करोड़ रुपए का था। भारत को विदेश से सोना खरीदने पर विदेशी मुद्रा डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। जब हम सोना कम खरीदते हैं, तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहता है और डॉलर की मांग कम हो जाती है। डॉलर की मांग घटने से विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए पर दबाव कम होता है, जिससे रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत बना रहता है। रुपए के मजबूत होने से कच्चे तेल और अन्य जरूरी चीजों का आयात सस्ता हो जाता है, क्योंकि भारत को इनके भुगतान के लिए कम रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इससे देश में महंगाई को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। 2025-26 में भारत ने पिछले कारोबारी साल के मुकाबले 4.76% कम सोना खरीदा, लेकिन सोने के इम्पोर्ट बिल में 24% तक का उछाल आया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी- सोने की तेजी से बढ़ती कीमतें। अभी सोने की कीमत करीब 1.43 लाख डॉलर प्रति किलो है। फिजिकल गोल्ड (जैसे गहने या सिक्के) के मुकाबले ETF में निवेश करना अधिक सुरक्षित और फायदेमंद है। जैसे इसकी चोरी का डर नहीं होता। लॉकर का खर्च नहीं लगता।

खरगे ने चुनाव...

उन्होंने सवाल किया- क्या बीजेपी को जिताने के लिए चुनावों के दौरान इन मतदाताओं के नाम हटाए गए? खरगे ने कहा कि बंगाल में SIR के दौरान हटाए गए नामों में से 91% नाम अपील के बाद फिर से जोड़ने पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि यही खेल दिल्ली में भी दोहराया जा रहा है। उनके मुताबिक, विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं की संख्या बढ़ाई गई थी। खरगे ने कहा कि इसके बाद ड्राफ्ट सूची से 47.56 लाख मतदाताओं के नाम गायब हो गए और 33 लाख अन्य मतदाताओं को नोटिस देने की तैयारी चल रही है।

पाकिस्तान ने...

इस विवाद के 6 घंटे बाद पाकिस्तान PMO ने X पर SCO की फोटो शेयर की है। इसमें PM मोदी भी नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने SCO समिट में सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पानी को कभी भी राजनीतिक दबाव या हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने साझा जल संसाधनों से जुड़े समझौतों को लेकर कहा कि इन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत ने हेग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि 1960 की सिंधु जल संधि कानूनी रूप से लागू है। किर्गिस्तान के बिश्केक में SCO समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अचानक मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और कुछ देर बातचीत की। दोनों के बीच अलग से द्विपक्षीय बैठक पहले से तय नहीं थी। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन भी दोनों नेताओं के साथ नजर आए। SCO समिट में अपने संबोधन के दौरान PM मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कार्रवाई की जरूरत बताई।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। उन्होंने आतंकवाद के पूरे तंत्र को खत्म करने पर जोर दिया। सिर्फ आतंकियों को पकड़ना या मारना काफी नहीं है। उन्हें पैसा कौन देता है, भर्ती कैसे होती है और कहां छिपते हैं, इस पूरे नेटवर्क को खत्म करना होगा। कुछ देशों के लिए आतंकवाद गलत और कुछ के लिए सही नहीं हो सकता। सभी को आतंकवाद के खिलाफ एक जैसी सख्त नीति अपनानी होगी।

पश्चिम एशिया में जंग का असर दूर-दूर तक पहुंचता है। देशों के बीच विवाद होने पर युद्ध करने के बजाय बातचीत और कूटनीति से रास्ता निकालना चाहिए। मोदी ने कहा कि भारत के लिए SCO अलग-अलग देशों की सभ्यता, संस्कृति और विचारों को जोड़ने वाला मंच भी है। मोदी ने मंगलवार को 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट में आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कार्रवाई की जरूरत बताई।

उन्होंने कहा कि सिर्फ आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, बल्कि आतंकवाद के पूरे तंत्र को खत्म करना होगा। मोदी ने कहा कि आतंकवाद की फंडिंग, आतंकियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों को खत्म करना जरूरी है। इस मुद्दे पर सभी देशों को एक सुर में बात करनी चाहिए और दोहरे रवैये की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मोदी ने मंगलवार को 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट में आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कार्रवाई की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि सिर्फ आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, बल्कि आतंकवाद के पूरे तंत्र को खत्म करना होगा। मोदी ने कहा कि आतंकवाद की फंडिंग, आतंकियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों को खत्म करना जरूरी है। इस मुद्दे पर सभी देशों को एक सुर में बात करनी चाहिए और दोहरे रवैये की कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

ममता बनर्जी की...

तब 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक लोगों ने भर्ती परीक्षा दी थी। इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए तक की घूस लेने का आरोप है। मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट को कई शिकायतें मिली थीं। भर्ती में अनियमितताओं के मामले में CBI ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी और SSC के कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया था।

अर्पिता पेशे से मॉडल थीं। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च, 2025 दिए आदेश में करीब 26,000 बर्खास्त शिक्षकों को राहत दी है। कोर्ट ने कहा था कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हुई है, वे नई चयन प्रक्रिया पूरी होने तक पढ़ाना जारी रख सकते हैं। हालांकि, उनका नाम 2016 के घोटाले मामले में नहीं आया हो। कोर्ट ने कहा- हम नहीं चाहते कि बच्चों की पढ़ाई कोर्ट के फैसले से बाधित हो।

दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में रजत पाटीदार-रिंकू फेल शमी ने 3 विकेट लिए

सूर्यवंशी की टीम ने सेंट्रल जोन 158 रन पर समेटा

मुकाबला

नई दिल्ली, एजेंसी

दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में वैभव सूर्यवंशी की उपकप्तानी वाली ईस्ट जोन ने सेंट्रल जोन को दूसरी पारी में 158 रन पर ऑलआउट कर दिया। सेंट्रल जोन के लिए अमन मोखाड़े ने 41 रन की सबसे बड़ी पारी खेली, जबकि अरशद खान ने 25 और हर्ष दुबे ने 24 रन बनाए। ईस्ट जोन की ओर से मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए।

सेंट्रल जोन की शुरुआत खराब रही और 37 रन तक टीम के तीन विकेट गिर गए। कप्तान रजत पाटीदार 5 और रिंकू सिंह 20 रन ही बना सके। 95 रन तक 7 विकेट गंवाने के बाद अरशद खान ने लोअर ऑर्डर के साथ मिलकर टीम को 150 रन के पार पहुंचाया, लेकिन 25 रन पर उनके आउट होते ही सेंट्रल जोन की पारी 158 रन पर सिमट गई।

सेंट्रल जोन की ओर से हर्ष दुबे ने 4, जबकि आर्यन पांडे और यश ठाकुर ने 3-3 विकेट लिए।

दूसरे सेमीफाइनल में साउथ जोन और नॉर्थ जोन आमने-सामने हैं। तीसरे दिन साउथ जोन की टीम पहली पारी में 312 रन पर ऑलआउट हो गई। कप्तान तिलक वर्मा ने 116 रन की नाबाद पारी खेली। उन्होंने 250 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौके लगाए। श्रेयस गोपाल ने 87 और नारायण जगदीशन ने 36 रन बनाए।

साउथ जोन की शुरुआत खराब रही। रितिक भुई 5 और शेख रशीद बिना खाता खोले आउट हुए। इसके बाद नारायण जगदीशन और तिलक वर्मा ने पारी संभाली। जगदीशन 36 रन बनाकर आउट हुए, जबकि तिलक ने श्रेयस गोपाल के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया।

शमी ने पूरे 900 विकेट किए

मोहम्मद शमी ने दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल के पहले दिन बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। ईस्ट जोन की ओर से खेल रहे शमी ने सेंट्रल जोन के खिलाफ 3 विकेट लेकर प्रोफेशनल क्रिकेट में अपने 900 विकेट पूरे किए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले सिर्फ छठे भारतीय गेंदबाज बने। शमी ने 36 साल की उम्र में यह मुकाम हासिल किया।

ईस्ट जोन से पहली पारी में सूर्यवंशी का अर्धशतक

सेंट्रल जोन और ईस्ट जोन की पहली पारी बराबरी पर रही। दोनों टीमों ने 266 रन बनाए। ईस्ट जोन के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 92 और अभिमन्यु ईश्वर ने 69 रन बनाए। दोनों ने पहले विकेट के लिए 161 रन जोड़े। हालांकि, इसके बाद ईस्ट जोन ने अगले 104 रन में अपने सभी विकेट गंवा दिए।

> ईस्ट जोन की ओर से मुकेश कुमार सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 12 ओवर में 44 रन देकर 4 विकेट लिए। मोहम्मद शमी ने 3, जबकि अभिजीत सरकार, अनुकूल रॉय और कुनैन कुरैशी ने 1-1 विकेट लिया।

अल्काराज की 139 दिन बाद जीत से वापसी

यूएस ओपन के दूसरे राउंड में पहुंचे, सबालेंका भी जीतीं

नई दिल्ली, एजेंसी

US ओपन 2026 में डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्काराज ने 139 दिन बाद सिंगल्स कोर्ट पर जीत के साथ वापसी की। अल्काराज कलाई की चोट के कारण चार महीने से ज्यादा समय तक टेनिस से दूर थे। स्पेन के खिलाड़ी ने न्यूयॉर्क के आर्थर एश स्टेडियम में रूस के रोमन सफीउलिन को 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वहीं, विमेंस सिंगल्स में दो बार की डिफेंडिंग चैंपियन आर्यना सबालेंका ने कैमिला ओसोरियो को 6-2, 6-4 से हराया।

अल्काराज ने चोट के कारण इस दौरान फ्रेंच ओपन और विंबलडन में हिस्सा नहीं लिया था। मैच के दौरान वह दाहिने हाथ पर कम्प्रेशन स्लीव पहनकर खेले।

अल्काराज की वापसी जीत शानदार रही, लेकिन सर्विस में उन्हें संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कहा कि चार महीने बाद वापसी में उन्हें मैच फिटनेस को लेकर थोड़ी चिंता थी। उन्हें यह भी संदेह था कि वह पांच सेट का मैच खेल पाएंगे या नहीं। जीत के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें लय हासिल करने के लिए अभी और मैच खेलने की जरूरत है।

कार्लोस अल्काराज 2004 से 2008 के बीच लगातार पांच बार खिताब जीतने वाले रोजर फेडरर के बाद यूएस ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब लगातार दूसरी बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बनने की कोशिश में हैं।

मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया इंस्टाग्राम पर इमोशनल पोस्ट की

लिखा- यह फैसला बेहद मुश्किल और दर्दनाक

नई दिल्ली। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल को अलविदा कह दिया है। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया पर हाथ से लिखे नोट की तस्वीर के साथ संन्यास का ऐलान किया।

39 साल के मेसी ने बताया कि फाइनल के 2 दिन बाद 21 जुलाई को ही उन्होंने संन्यास का फैसला लिख लिया था। उनका आखिरी मैच वर्ल्ड कप फाइनल था, जिसमें अर्जेंटीना को स्पेन से हार मिली थी।

मेसी ने लिखा कि उनके पिता जॉर्ज मेसी की मौत के बाद उन्हें लगा कि अर्जेंटीना के लिए करियर खत्म करने का यही सही समय है।' जॉर्ज मेसी का 8 अगस्त को सेंट्रल अर्जेंटीना के रोसारियो शहर के एक अस्पताल में निधन हुआ था। वे 68 साल के थे।

मेसी ने लिखा, 'यह फैसला लेना तकलीफदेह था और आज भी दिल के अंदर तक दुख देता है, लेकिन मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है। मैंने हमेशा अपना सब कुछ दिया है। सिर्फ उन पिछले कुछ सालों में नहीं, जब हमने सब कुछ जीता, बल्कि उससे पहले भी।'

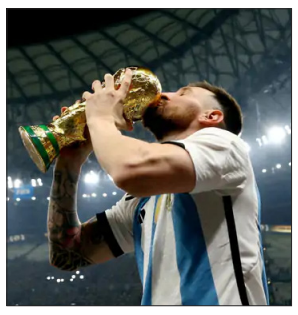

मैंने इस जर्सी के लिए हमेशा संघर्ष किया। मैदान पर अपना सब कुछ छोड़ा, ताकि आपको खुशी दे सकूं। फुटबॉल के जरिए आपको अर्जेंटीनियन होने पर गर्व महसूस करा सकूं।

समय कम बचा है और अध्याय खत्म होते हैं। यह भी ऐसा ही एक अध्याय है, जो मुझे बहुत दुख देता है। मुझे राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बनना पसंद था, पसंद है और हमेशा रहेगा। मैंने अपने पास मौजूद सब कुछ दे दिया है। अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसके अलावा, कई बेहतरीन युवा खिलाड़ी आ रहे हैं, जो यहां होने के हकदार हैं। पिता के निधन के बाद कहा था- ज्यादा नहीं खेल पाऊंगा

मेसी ने अपने पिता की मौत के बाद एक पोस्ट में लिखा था कि उन्हें इस बात को लेकर 'काफी संदेह' था कि वे ज्यादा समय तक अर्जेंटीना के लिए खेल पाएंगे या नहीं।

उन्होंने स्पेन के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में अपने प्रदर्शन को लेकर भी लिखा था, 'मेरे पैर अब आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इस बार मैंने अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे जाने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका।'

लाबुशेन ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम से बाहर

जिम्बाब्वे-साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए नहीं चुने गए, जोएल डेविस को मौका, स्टार्क-कमिंस की वापसी

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका दौरे के लिए 17 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। खराब फॉर्म से जूझ रहे मार्नस लाबुशेन को टीम में जगह नहीं मिली है। वहीं जोएल डेविस पहली बार वनडे टीम में चुने गए हैं।

मिचेल मार्श और ट्रैविस हेड की वापसी हुई है, जबकि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम से जुड़ेंगे। लाबुशेन लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत के खिलाफ नाबाद अर्धशतक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि, मौजूदा फॉर्म को देखते हुए उन्हें इस दौरे के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। लाबुशेन ने पिछली 18 वनडे पारियों में 21.87 की औसत से रन बनाए हैं।

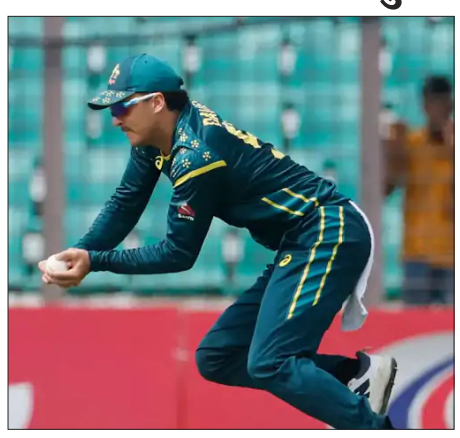

जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन वनडे मैचों में मार्श टीम की कप्तानी करेंगे। रेगुलर कप्तान पैट कमिंस साउथ अफ्रीका सीरीज में टीम से जुड़ेंगे। हालांकि कमिंस ने संकेत दिया है कि वे साउथ अफ्रीका के सभी तीन वनडे नहीं खेलेंगे, ऐसे में मार्श फिर कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। स्टार्क भी साउथ अफ्रीका सीरीज में वनडे टीम में वापसी करेंगे। जोश हेजलवुड दोनों सीरीज के लिए टीम में हैं। स्पेंसर जॉनसन भी एक साल से ज्यादा समय बाद वनडे क्रिकेट में वापसी करेंगे, जबकि बिली स्टेनलेक को भी तेज गेंदबाजी आक्रमण में शामिल किया गया है।

15 सितंबर से जिम्बाब्वे में सीरीज

ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच तीन वनडे 15, 18 और 20 सितंबर को हरारे में खेले जाएंगे। इसके बाद साउथ अफ्रीका में 24 सितंबर को डरबन, 27 सितंबर को जोहान्सबर्ग और 30 सितंबर को पोटचेफस्ट्रूम में तीन वनडे होंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन टेस्ट मैच खेलने हैं। पहला टेस्ट 9 अक्टूबर से डरबन में शुरू होगा।

जून में पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ 4 वनडे खेले ओली पीक को भी टीम में जगह दी गई है।

जोएल डेविस को पहली बार वनडे टीम में जगह

ऑलराउंडर जोएल डेविस को पहली बार ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम में चुना गया है। उन्होंने जून में बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। युवा ओली पीक भी टीम में अपनी जगह बनाए रखने में सफल रहे हैं। कूपर कोनोली को भी टीम में बरकरार रखा गया है। सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने कहा कि जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में होने वाली छह मैचों की सीरीज अगले साल के वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। 2027 का वनडे वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाना है।

मनोरंजन

शादी के 5 महीने बाद अलग हुए, पहली पत्नी जैस्मिन से 2020 में अलग हुए थे

रैपर बादशाह ने दूसरी पत्नी ईशा रिखी से लिया तलाक

नई दिल्ली, एजेंसी

रैपर बादशाह और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी ने अपनी शादी के 5 महीने बाद ही एक-दूसरे से अलग होने का ऐलान कर दिया है। दोनों ने सोमवार रात अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर तलाक की पुष्टि की। बादशाह ने अपनी पोस्ट में कहा कि यह फैसला दोनों की आपसी सहमति से लिया गया है। उन्होंने फैंस और मीडिया से इस समय में उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने और किसी भी तरह का अंदाजा न लगाने का अनुरोध किया है।

इंस्टाग्राम पोस्ट में क्या लिखा

बादशाह और उनकी पहली पत्नी जैस्मिन मसीह।

पोस्ट में बादशाह ने लिखा कि वे और ईशा रिखी आपसी सम्मान के साथ अलग-अलग रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं। बादशाह ने लिखा, ₹हमारा यह फैसला आपसी सहमति से लिया गया है। हम सभी से गुजारिश करते हैं कि इस समय हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखें। इस मुद्दे पर हमारा यह पहला और आखिरी बयान है, इसलिए हमारी रिलेशनशिप को लेकर आगे कोई अंदाजा न लगाया जाए। ईशा रिखी ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर यही बयान शेयर किया है। जुलाई से सामने आ रही थीं अनबन की खबरें बादशाह और ईशा रिखी के रिश्ते में तनाव की खबरें जुलाई के महीने में आनी शुरू हुई थीं। 26 जुलाई को ईशा ने बादशाह के साथ अपनी कई तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए एक पोस्ट लिखी थी।

> बादशाह का दूसरा तलाक, पहली पत्नी से है एक बेटी यह रैपर बादशाह का दूसरा तलाक है। इससे पहले उन्होंने 2012 में जैस्मिन मसीह से शादी की थी। साल 2017 में दोनों की एक बेटी हुई, जिसका नाम जेसेमी ग्रेस मसीह सिंह है। हालांकि मतभेदों के बाद बादशाह और जैस्मिन साल 2020 में एक-दूसरे से अलग हो गए थे। इसके बाद बादशाह की जिंदगी में ईशा रिखी की एंट्री हुई थी।

नेपाल बाढ़ में फंसी एक्ट्रेस मानसी भारत लौटीं

एयरपोर्ट पर बेटी को गले लगाकर भावुक हुईं

नई दिल्ली। नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्ट्रेस मानसी पारेख कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई भीषण बाढ़ के बीच फंसने के बाद सुरक्षित मुंबई लौट आई हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर वे अपने पति और बेटी को गले लगाकर भावुक दिखाई दीं। तिब्बत में भूस्खलन होने के कारण उन्हें 4 घंटे तक बस में इंतजार करना पड़ा। इसके बाद वे पैदल खराब रास्ता पार कर नेपाल सीमा पहुंचीं और काठमांडू होते हुए मुंबई अपने परिवार के पास पहुंचीं।

मानसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस पूरे अनुभव को शेयर करते हुए जंग जीतने जैसा बताया है।

पैदल पार किया लैंडस्लाइड वाला रास्ता एक्ट्रेस मानसी पारेख ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। भूस्खलन हकी वजह से रास्ता साफ होने तक उनकी बस 4 घंटे तक वहीं खड़ी रही। इसके बाद करीब 40 मील का सफर तय करके उनकी टीम नेपाल बॉर्डर पहुंची।

दिल्ली में नाबालिग से गैंगरेप पर भड़कीं भूमि पेडनेकर

बोलीं- शर्मनाक, बार-बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं?

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में चलती स्लीपर बस के अंदर 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंगरेप के मामले पर एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने कड़ा विरोध जताया है।

उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर देश में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। भूमि ने लिखा कि बार-बार ऐसी घटनाएं कैसे हो सकती हैं, यह बेहद शर्मनाक है।

गलत बस में बिठाकर नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म दिल्ली पुलिस के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की रहने वाली 11वीं की छात्रा अपने घर से नोएडा जाने के लिए निकली थी। ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर बारिश और अंधेरा होने की वजह से वह फंस गई।

इसी दौरान आई एक प्राइवेट स्लीपर बस के कंडक्टर ने उसे झांसा देकर बस में बिठा लिया। बस में कोई अन्य सवारी नहीं थी। रास्ता शुरू होते ही बस ड्राइवर और कंडक्टर ने नाबालिग के साथ दरिंदगी की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना 4 अगस्त की है, पुलिस ने 31 अगस्त को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बस को तिमारपुर से जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला सुरक्षा और स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर पहले भी बोल चुकी हैं भूमि यह पहला मौका नहीं है जब भूमि पेडनेकर ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों और सुरक्षा के मुद्दे पर बात की है।

पैपराजी पर भड़कीं करीना

बार-बार राइट-लेफ्ट जाने को कहा तो बोलीं- मैंने हील्स पहनी है

नई दिल्ली। एक्ट्रेस करीना कपूर खान अपनी आने वाली फिल्म 'दायरा' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पैपराजी पर भड़क गईं। मुंबई में आयोजित इस इवेंट के दौरान जब वे पैपराजी को पोज दे रही थीं, तब उन्हें गुस्सा आ गया। दरअसल फोटो क्लिक करवाने के दौरान पैपराजी उन्हें लगातार राइट और लेफ्ट होने के लिए कह रहे थे। इससे परेशान होकर करीना ने पैपराजी को फटकार लगाई और कहा कि कभी इधर, कभी उधर, मैंने हील्स पहनी है। बार-बार एंगल बदलने की हिदायत से करीना असहज हो गईं। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आई। करीना ने पैपराजी को टोकते हुए कहा कि वे हील्स पहनकर बार-बार इधर-उधर नहीं घूम सकतीं। सवाल सुनते ही डायरेक्टर की तरफ किया इशारा इवेंट में रिपोर्टर ने करीना कपूर से पूछा कि सोशल मीडिया पर एक्ट्रेसेस के कपड़ों और उनके रिप्रेजेंटेशन को लेकर काफी ट्रोलिंग होती है, ऐसे में एक एक्ट्रेस होने के नाते उनकी क्या सीमाएं होनी चाहिए। सवाल पूरा सुनते ही करीना ने खुद बोलने के बजाय माइक डायरेक्टर मेघना गुलजार की तरफ बढ़ा दिया।

इसी इवेंट में कृति सेनन की ट्रोलिंग का सवाल टाला

ट्रेलर लॉन्च के इसी इवेंट में एक्ट्रेस कृति सेनन के रक्षाबंधन एडवर्टाइजमेंट में कपड़ों को लेकर शुरू हुए विवाद पर करीना कपूर ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया था। करीना से इस विवाद और एक्ट्रेसेस की सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर सवाल पूछा, तो उन्होंने इस सवाल पर चुप्पी साधे रखी। करीना ने इस सवाल का जवाब पास में बैठीं डायरेक्टर मेघना गुलजार से देने को कहा।

बारटेंडर ने मुंडवा दिया सिर, युवती कथित तौर पर एक फर्जी पहचान पत्र दिखाकर बार में दाखिल हुई

थाईलैंड में बार का बिल न चुकाने पर महिला के साथ बदसलूकी

आरोप

बैंकॉक, एजेंसी

गलतियों या धोखाधड़ी की सजा क्या इतनी अपमानजनक होनी चाहिए कि किसी इंसान की व्यक्तिगत गरिमा ही तार-तार हो जाए? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से सामने आए एक चौंकाने वाले मामले ने इसी सवाल को लेकर इंटरनेट पर नैतिकता, मर्यादा और कानून के दायरे पर एक गंभीर बहस छेड़ दी है। बार में हजारों रुपयों का बिल न चुका पाने पर एक युवती के सिर के बाल मुंडवाने का वीडियो सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। वायरल प्रेस के

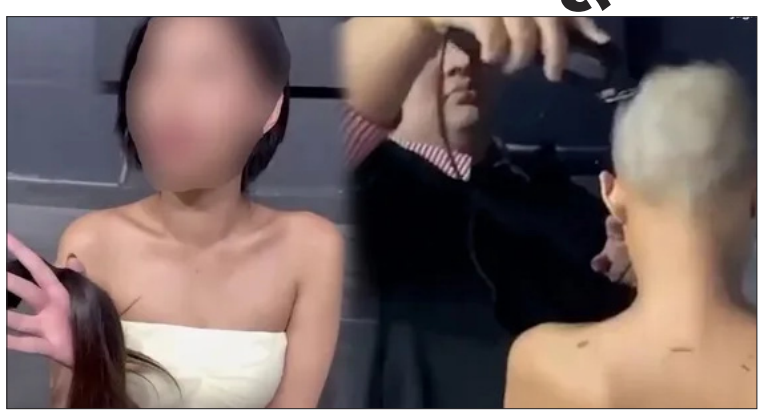

अनुसार, यह घटना 25 अगस्त को बैंकॉक के पिंकलाओ इलाके के एक लोकप्रिय बार में घटी। आरोप है कि यह युवती पहले भी इस इलाके के क्लबों और रेस्तरां में बिना बिल चुकाए भागने के लिए जानी जाती थी।

युवती कथित तौर पर एक फर्जी पहचान पत्र दिखाकर बार में दाखिल हुई। वहां उसने करीब 60,000 थाई बाथ का बिल बना लिया। इसके बाद उसने बिना भुगतान किए चुपके से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारियों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और बिल चुकाने का दबाव बनाया।

पुलिस से बचने के लिए बालों का सौदा

जब युवती के पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं निकले, तो उसने पुलिस में जाने से बचने के लिए एक अजीबोगरीब और अपमानजनक शर्त पर अपने सिर के बाल मुंडवाने सहमति जताई।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में सफेद ड्रेस पहने यह युवती एक तथाकथित हेयर परचेज कॉन्ट्रैक्ट पर सहमति देती दिख रही है। कैमरे के पीछे से एक व्यक्ति यह कहता सुनाई दे रहा है कि मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा रहा हूं। यह बाजार भाव है। मैं तुम्हारे लिए यह जोड़ रहा हूं और कुछ अतिरिक्त पैसे भी लगा रहा हूं, ठीक है? इसके बाद वीडियो में बारटेंडर को एक इलेक्ट्रिक ट्रिमर से युवती के कंधे तक लंबे घने बालों को पूरी तरह मुंडते हुए देखा जा सकता है। दावा किया गया कि इन बालों को बाद में दान किया जाएगा।

थाईलैंड में भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेकर सिर मुंडवाने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले 10 मई को बैंकॉक में मैडम लोह के नाम से पहचाने जाने वाले अब्दुललोह नामक व्यक्ति को भी इसी तरह की सजा दी गई थी। उन पर धार्मिक आयतों का मजाक उड़ाने का आरोप था, जिसके बाद भारी भीड़ ने उन्हें घेर लिया था। तीन घंटे चले गतिरोध के बाद पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने माफी मांगी और अपना सिर मुंडवाया था।

सामाजिक संस्थाओं ने उठाए सवाल

इस घटना का वीडियो वायरल होते ही लोगों की राय बंट गई। जहां कुछ लोगों ने इसे युवती के धोखे की सजा बताया, वहीं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने इसे अमानवीय और गैर-कानूनी करार दिया।

बाल शोषण और मानवाधिकारों पर काम करने वाले थाईलैंड के 'बी वन फाउंडेशन' की संस्थापक चलिदा 'टोन ओर' फलामत ने कहा कि बार प्रबंधन ने हद पार कर दी है। चलिदा के अनुसार, मजबूरी और दबाव में कराया गया कोई भी अनुबंध कानूनन शून्य होता है।

किसी की मर्जी के बिना या दबाव डालकर सिर मुंडवाना सीधे तौर पर मारपीट, जबरन वसूली और गैर-कानूनी तरीके से बंधक बनाने का मामला बनता है। उन्होंने बताया कि बार प्रबंधन ने संपर्क कर माना कि यह कदम मैनेजर ने गुस्से और जल्दबाजी में उठाया था और वे परिवार से मुआवजे की बात करेंगे। इस मामले की जांच के लिए थाईलैंड के सामाजिक विकास और मानव सुरक्षा मंत्रालय से भी अपील की गई है।

नेपाल में एक ही घर से 24 शव बरामद

काठमांडू, एजेंसी

नेपाल में आई भीषण बाढ़ को कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन तबाही का खौफनाक मंजर अब भी कायम है। बिखरे हुए मलबे के बीच जिंदगियां तलाशने का अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। करीब चार हजार लोग अभी भी लापता हैं।

रेस्क्यू एजेंसियों के अनुसार, अब तक करीब 939 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को नुवाकोट जिले में रेस्क्यू के दौरान एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई।

नेपाल के एक न्यूज वेबसाइट के अनुसार, नुवाकोट जिले के भोटे कोशी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बिदुर नगर पालिका-10 (वेत्रवंती) में एक ही घर के मलबे से 24 शव निकाले गए हैं। नुवाकोट के एसपी बिपिन रेग्मी ने बताया कि बरामद किए गए शवों में 13 महिलाएं, 11 पुरुष और एक बच्चा

अब तक 939 लोगों की मौत 4000 से ज्यादा अभी भी लापता

शामिल है। फिलहाल शवों की पहचान नहीं हो सकी है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए काठमांडू के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग अस्पताल भेज दिया गया है। त्रिशूली सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल राजेंद्र दवाड़ी के सही समय पर लिए गए फैसले ने करीब 900 छात्रों की जान बचा ली। बाढ़ की चेतावनी मिलते ही प्रिंसिपल दवाड़ी ने तुरंत स्कूल खाली कराया और सभी मौजूद छात्रों को पास की एक सुरक्षित पहाड़ी पर पहुंचा दिया।

फास्ट न्यूज

ज्वेलरी कंपनियों के स्टॉक्स 6% तक टूटे

नई दिल्ली। शेयर बाजार में आज यानी 1 सितंबर को मामूली गिरावट रही। सेंसेक्स 13 अंक की गिरावट के साथ 76,944 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 25 अंक की गिरावट रही, ये 24,056 पर बंद हुआ। ऑटो, फार्मा, बैंकिंग और रियल्टी शेयर्स में ज्यादा बिकवाली रही। PM नरेंद्र मोदी के लोगों से गैर-जरूरी सोना न खरीदने की अपील के बाद ज्वेलरी कंपनियों से जुड़े स्टॉक्स में गिरावट है।

सुभाष चंद्रा केस में एनसीएलटी के आदेश पर रोक

नई दिल्ली। NCLT की 5-सदस्यीय बेंच ने मंगलवार को जी ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा के रीपेमेंट प्लान पर रोक लगा दी है। 25 अगस्त के आदेश में उनके 22,000 करोड़ से ज्यादा के बकाए कर्ज के बदले सिर्फ 6.25 करोड़ चुकाने के प्लान को मंजूरी दी गई थी। कोर्ट ने सुभाष चंद्रा पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी किसी भी संपत्ति को बेचने या ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है। सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किया है।

ओरैकल 10 हजार कर्मचारियों की छंटनी करेगी

नई दिल्ली। टेक कंपनी ओरेकल दुनियाभर में अपने लगभग 10 हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। इससे भारत में काम करने वाले कर्मचारी भी प्रभावित हो सकते हैं। कंपनी यह कदम क्लाउड और AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ते खर्च को संतुलित करने और अपनी लागत घटाने के लिए उठा रही है। ओरेकल मैनेजमेंट ने अपनी अलग-अलग टीमों से अपने खर्च में कटौती करने के रास्ते तलाशने को कहा है।

ईयू में अब चैटजीपीटी पर कानूनी पहरा

एआई मॉडल को करना पड़ेगा कड़े नियमों का सामना

ब्रुसेल्स, एजेंसी

यूरोपीय संघ ने सोमवार को चैटजीपीटी को उन डिजिटल सेवाओं की सूची में शामिल कर लिया है, जिन पर अब अधिक कानूनी निगरानी रखी जाएगी। किसी एआई चैटबॉट को पहली बार इतने कड़े नियमों के दायरे में लाया गया है।

ब्रुसेल्स ने चैटजीपीटी के साथ-साथ रेडिट और रोब्लॉक्स को भी वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में नामित किया है। इस लेबल का मतलब है कि अब इन कंपनियों को अतिरिक्त कानूनी दायित्वों और सख्त निगरानी का पालन करना होगा। यूरोपीय संघ की प्रौद्योगिकी प्रमुख हेना विर्कुनेन ने कहा कि चैटजीपीटी, रेडिट और रोब्लॉक्स को अब यूरोपीय संघ में उच्च स्तर की निगरानी और जवाबदेही के मानकों पर खरा उतरना होगा। यह कदम हमारे नागरिकों और समाज पर उनके व्यापक प्रभाव को देखते हुए उठाया गया है। यूरोपीय संघ के नियमों के अनुसार, 27 देशों के इस समूह में जिन प्लेटफॉर्म्स या सर्च इंजनों के 4.5 करोड़ से अधिक मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, उन पर यह नियम लागू होता है। यूरोपीय आयोग ने बताया कि इन तीनों प्लेटफॉर्म्स ने जानकारी दी थी कि वे इस आंकड़े को पार कर चुके हैं।

अब इन तीनों कंपनियों के पास डिजिटल सर्विसेज एक्ट के तहत अतिरिक्त दायित्वों का पालन करने के लिए चार महीने का समय है। डिजिटल सर्विसेज एक्ट एक ऐसा कानून है जिसे यूरोपीय संघ ने बिग टेक कंपनियों पर लगाम कसने और ऑनलाइन कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए लागू किया है।

नौ चरणों वाली प्रक्रिया की दी जानकारी, तबाही का मंजर ऐसा है कि 3916 से ज्यादा लोग अभी भी लापता

नेपाल त्रासदी : लावारिस शवों की शिनाख्त के लिए आगे आया भारत

काठमांडू, एजेंसी

तिब्बत सीमा से सटे नेपाल के पहाड़ी इलाकों में प्रकृति ने ऐसा तांडव मचाया है जिसकी कल्पना भी डरावनी है। इस भीषण बाढ़ में अब तक 987 से अधिक लोगों की मोत हो चुकी हैं। तबाही का मंजर ऐसा है कि 3916 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, लापता लोगों में 275 भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के 128 लोग शामिल हैं। इनमें से अधिकांश श्रद्धालु हैं जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे, लेकिन रास्ते में ही इस आपदा का शिकार हो गए। पहाड़ों से बहकर आ रहे शवों के कारण नेपाल प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों पर काफी दबाव है। नेपाल में स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय परिवारों को

अस्पतालों के मुर्दाघरों में तिल रखने की भी जगह नहीं बची है। अभी तक यह पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है कि मिले शवों में कितने विदेशी सैलानी या तीर्थयात्री हैं। अपनों की तलाश में भटकते बदहवास रिश्तेदारों की मदद के लिए सरकार ने बरामद शवों की तस्वीरों का एक पावरपॉइंट स्लाइड शो तैयार किया है, ताकि वे अपने प्रियजनों की पहचान कर सकें।

उनके प्रियजनों के शवों की पहचान करने में सहायता के लिए चरण-दर-चरण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दूतावास ने बताया कि नेपाल सरकार मृतकों की तस्वीरें और विवरण जारी कर रही है, जिन्हें वेबलिंक के माध्यम से देखा जा सकता है। यदि कोई परिवार तस्वीरों के माध्यम से शव की पहचान करने में सक्षम होता है, तो दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करके पार्थिव शरीर सौंपने और स्वदेश वापसी की प्रक्रिया में पूरी मदद करेगा। नेपाल सरकार ने शवों पर दावा करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की है, जो इस प्रकार है। दूतावास ने एक बयान में कहा कि नेपाल सरकार ने स्वास्थ्य जोखिमों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में शवों को अस्थायी रूप से दफनाया है। ऐसे शवों की पहचान के लिए प्रथम-श्रेणी के रिश्तेदारों के साथ डीएनए मिलान की आवश्यकता होगी। जिन मामलों में पहचान संभव नहीं हो पाई है या शवों को अस्थायी रूप से दफना दिया गया है, वहां नेपाल के अधिकारी डीएनए मिलान की सुविधा प्रदान करेंगे। नेपाली अधिकारी डीएनए प्रोफाइल बनाने के लिए शवों से डीएनए के नमूने ले रहे हैं। मिलान के लिए, मृतकों के करीबी रिश्तेदार अपना डीएनए प्रोफाइल ईमेल dnacodis@nepalpolice.gov.np पर भेज सकते हैं या नेपाली अधिकारियों द्वारा मांगी गई प्रारंभिक जानकारी के साथ अपने खून के नमूने दे सकते हैं।

भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर पर करें संपर्क

सुविधा और मदद के लिए प्रथम-श्रेणी के रिश्तेदारों की डीएनए प्रोफाइल को भारतीय दूतावास की ईमेल आईडी eoikathmandufloodsupport@gmail.com पर भी कॉपी किया जा सकता है।

डीएनए प्रोफाइलिंग से संबंधित अन्य जानकारी नेपाल पुलिस की वेबसाइट https://www.nepalpolice.gov.np/ और उनके हेल्पलाइन नंबर +977 9841616095 पर उपलब्ध है।

किसी भी अतिरिक्त सहायता या पूछताछ के लिए, भारतीय दूतावास से व्हाट्सएप नंबरों +977 9851316807, +977 9709107500, या +977 9810326117 पर संपर्क किया जा सकता है।

एआई से सीधे जवाब मिलने से वेबसाइट ट्रैफिक घटा, वेबसाइटें एआई क्रॉलर्स को जानकारी लेने से रोक रही

एआई और वेबसाइट के बीच छिड़ा 'डिजिटल युद्ध'

मेलबर्न, एजेंसी

इंटरनेट पर किसी जानकारी की तलाश में अब लोग पहले की तरह वेबसाइटों पर जाने के बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से सीधे सवाल पूछ रहे हैं। कुछ सेकंड में जवाब मिल जाता है और कई बार वेबसाइट खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन सुविधा का यह बढ़ता चलन इंटरनेट की उस व्यवस्था के लिए परेशानी पैदा कर रहा है, जिस पर पिछले करीब तीन दशक से वेबसाइटें और सर्च इंजन टिके हुए हैं।

इंटरनेट पर एआई से जुड़े बाट और क्रालर अब बड़ी मात्रा में वेबसाइटों की जानकारी खंगाल रहे हैं। क्लाउडफ्लेयर के अनुमान के

मुताबिक वेब ट्रैफिक में एआई बाट्स की हिस्सेदारी अब काफी बढ़ चुकी है। इसका एक दूसरा असर भी सामने आ रहा है।

जब अच्छी वेबसाइटें एआई क्रालर को रोकेंगी और कम भरोसेमंद वेबसाइटें उन्हें खुला छोड़ देंगी तो एआई को मिलने वाली जानकारी का संतुलन बिगड़ सकता है। ऐसे में एआई के जवाबों में बेहतर स्रोतों की जगह कम गुणवत्ता वाली वेबसाइटों की जानकारी बढ़ने का खतरा है। सर्च की दुनिया में अब एक नए खतरे की चर्चा हो रही है, जिसे गूगल जीरो कहा जा रहा है। इसका मतलब है ऐसी स्थिति, जब लोग गूगल पर खोज करने के बाद वेबसाइट खोलने के बजाय गूगल के एआई से मिले जवाब को ही पर्याप्त मान लें। एआई से सीधे जवाब मिलना यूजर के लिए सुविधाजनक है।

एआई टूल जैसे चैटजीपीटी और गूगल के एआई फीचर बड़ी संख्या में वेबसाइटों से जानकारी लेकर अपने जवाब तैयार करते हैं। समस्या यह है कि जब यूजर को जवाब सीधे एआई से मिल जाता है तो वह मूल वेबसाइट पर क्लिक नहीं करता। इससे वेबसाइटों का ट्रैफिक घटता है और विज्ञापन से होने वाली कमाई पर भी असर पड़ता है।

टूट रहा है इंटरनेट का पुराना समझौता

नतीजा यह है कि कई वेबसाइट संचालक अब एआई कंपनियों के क्रालर को साइट से जानकारी लेने से रोक रहे हैं। यानी जिस वेबसाइट की जानकारी से एआई जवाब देना सीखता है, वही वेबसाइट एआई से दूरी बनाने लगी है।

इंटरनेट के शुरुआती दौर में सर्च इंजन और वेबसाइटों के बीच एक तरह का अनकहा समझौता था। सर्च इंजन वेबसाइटों की जानकारी को खोजकर अपने नतीजों में दिखाते थे और बदले में यूजर को उस वेबसाइट का लिंक देते थे। इससे वेबसाइट को पाठक और विज्ञापन के जरिए कमाई मिलती थी। एआई के आने से यह व्यवस्था बदल रही है।

एआई किसी वेबसाइट की जानकारी पढ़कर उसका सार सीधे यूजर को बता देता है। ऐसे में बसाइट तक पहुंचने की जरूरत कम हो जाती है। वेबसाइट संचालकों के लिए यही सबसे बड़ी चिंता है। उनका तर्क है कि अगर लोग वेबसाइट पर आएंगे ही नहीं तो अच्छी और भरोसेमंद सामग्री तैयार करने का खर्च कैसे निकलेगा।

डीलर 15 सितंबर से 2000 क्विंटल चीनी रख सकेंगे

स्टॉक 30 दिन से ज्यादा नहीं रख सकेंगे

नई दिल्ली, एजेंसी

देश में चीनी जल्द ही सस्ती हो सकती है। केंद्र सरकार ने जमाखोरी रोकने और त्योहारों से पहले कीमतें काबू करने के लिए चीनी डीलरों के लिए स्टॉक लिमिट घटाने का ऐलान किया है।

खाद्य मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक, 15 सितंबर से चीनी व्यापारी और डीलर्स अधिकतम 2,000 क्विंटल ही स्टॉक रख सकेंगे। यह नया नियम 30 नवंबर 2026 तक पूरे देश में लागू रहेगा।

नए नियमों के मुताबिक, डीलर्स को अब स्टॉक मिलने की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक चीनी रखने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, वे देश में किसी भी स्थान पर एक समय में 2000 क्विंटल से ज्यादा चीनी नहीं रख सकेंगे।

सरकार का उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी पर लगाम लगाना है, ताकि

बाजार में आपूर्ति सुचारू रहे और आम उपभोक्ताओं को सही दाम पर चीनी उपलब्ध हो सके।

कोलकाता के लिए पुरानी 4000 क्विंटल की स्टॉक लिमिट जारी रहेगी। क्योंकि, कोलकाता में यूपी और महाराष्ट्र से चीनी आती है और यहीं से पश्चिम बंगाल समेत पूरे पूर्वोत्तर भारत में सप्लाई होती है। सप्लाई चेन में कोई रुकावट न आए, इसलिए इन क्षेत्रों को राहत दी गई है। सरकार चीनी मिलों, डीलरों और व्यापारियों के गोदामों की सख्त निगरानी और फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही है, जहां कई अनियमितताएं और अघोषित स्टॉक पकड़े गए हैं।

आरोप : न्यूयॉर्क में रेप और अपहरण का दोषी पाया गया, नागरिकता आवेदन में आपराधिक इतिहास छिपाया था

भारतीय मूल के व्यक्ति की यूएस नागरिकता 15 साल बाद रद

वॉशिंगटन, एजेंसी

भारतीय मूल के एक व्यक्ति की अमेरिकी नागरिकता रद कर दी गई है। इस व्यक्ति को रेप के मामले में दोषी पाया गया है। टैक्सी ड्राइवर गुरमीत सिंह (55) पर आरोप है कि उसने 2011 में न्यूयॉर्क में चाकू की नोक पर एक महिला यात्री का अपहरण किया और उसके साथ रेप किया। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, 2014 में हिंसक हमले का दोषी पाए जाने के बाद उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। अमेरिकी एजेंसी ने एक बयान में कहा कि गुरमीत ने अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन करते समय अपने आपराधिक अतीत को

छिपाया था। उसे हमले के कुछ महीनों बाद नागरिकता मिली थी।

मूल रूप से भारत के रहने वाला गुरमीत सिंह फरवरी 1992 में ज्यादा से ज्यादा छह महीने की अवधि के लिए विजिटर के तौर पर अमेरिका पहुंचा था। न्याय विभाग के अनुसार, इसके बाद वह बिना इजाजत के कई सालों तक अमेरिका में रहा, जब तक कि जून 2000 में परिवार-आधारित आप्रवासी वीजा याचिका के जरिए उसे स्थायी निवासी बनने की मंजूरी नहीं मिल गई। मई 2011 में अमेरिकी नागरिक बनने के लिए आवेदन करने से कुछ हफ्ते पहले टैक्सी ड्राइवर रहे सिंह एक महिला यात्री को ले जा रहा था और ये महिला घर जाते समय रास्ते में सो गई थी।

'नागरिकता लेते वक्त छिपाया आपराधिक बैकग्राउंड'

अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कहा कि भारत के रहने वाले और रेप के दोषी गुरमीत अब अमेरिकी नागरिक नही है। ब्लैंच ने कहा, ₹भारत के दोषी बलात्कारी गुरमीत सिंह अब अमेरिकी नागरिक नहीं रहे। उन्होंने नागरिकता पाने की प्रक्रिया के दौरान बलात्कार और अपहरण की बात छिपाई थी और अब एक फेडरल कोर्ट ने उनकी नागरिकता रद कर दी है। उन्होंने आगे कहा, विभाग ने इस मामले को अंजाम तक पहुंचाया है और हम डीनेचुरलाइजेशन (नागरिकता रद करने) के मामलों पर तेजी से काम करना जारी रखेंगे। धोखाधड़ी से हासिल की गई नागरिकता अपराधियों को सजा से नहीं बचा पाएगी।

खबरों के मुताबिक, गुरमीत ने अपनी नागरिकता पाने की प्रक्रिया के दौरान इन कामों को छिपाया, जिसके चलते अक्टूबर 2011 में उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल गई। नागरिकता मिलने के बाद न्यूयॉर्क में सिंह को रेप (फर्स्ट डिग्री) और यौन मंशा से किए गए अपराध के तौर पर अपहरण (सेकंड डिग्री) का दोषी ठहराया गया और 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई।

मारे गए 12 लोगों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल : जेलेंस्की

कीव, एजेंसी

रूस की ओर से यूक्रेन में रातभर किए गए बड़े हवाई हमले में मारे गए 12 लोगों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ₹कुल 12 लोग मारे गए, जिनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है और हमले में दर्जनों अन्य लोग घायल हुए हैं। जिन लोगों ने अपने परिवार और प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं।

हमले के बाद कई इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। जेलेंस्की ने बताया कि कीव और आसपास के क्षेत्र में ही करीब 350 राहतकर्मी हमले के बाद के हालात से निपटने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि हमले में बड़ी संख्या में जेट से चलने वाले ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। आवासीय इमारतों और नागरिक

बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। जेलेंस्की के अनुसार, बोरिस्पिल में पांच मंजिला आवासीय इमारत क्षतिग्रस्त हुई और 50 लोगों को वहां से निकाला गया। शहर में चार लोगों की मौत हुई और 13 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बताया कि ओडेसा और आसपास के क्षेत्र में भी पिछली शाम से निर्देशित हवाई बमों और ड्रोन से हमले जारी हैं। इन हमलों के कारण हजारों परिवार बिजली के बिना रह गए हैं और बिजली आपूर्ति बहाल करने का काम जारी है।

उन्होंने कहा कि रोमानिया से लगी सीमा पर एक सीमा चौकी को जानबूझकर निशाना बनाया गया। निर्यात से जुड़े बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676